

पहाड़ की चोटियों से समुद्र तट तक योगमय हुई दुनिया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को पूरी दुनिया योगमय दिखी। पहाड़ की ऊँची चोटियों से लेकर समुद्र तट तक, कोलकाता से कैलिफोर्निया तक लोगों ने योग किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोगों की मौजूदगी में योग के माध्यम से दुनिया को शांति से लेकर स्वास्थ्य, मानव एकता, आंतरिक संतुलन व सामूहिक कल्याण का मंत्र दिया। दुनिया में जारी युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि वैश्विक शांति का मार्ग प्रशस्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने हर आयु वर्ग के लोगों से योग को अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलोंग में वायु सेना के एडवॉसट लैंडिंग ग्राउंड में योग सत्र में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में 35 हजार लोगों संग किया योगाभ्यास

कहा-70 की उम्र में 50 जैसा दिखें, योग इसमें मददगार, यह सबको जोड़ता है

राष्ट्रपति मुर्मू ने जबलपुर में किया योग, बताया, विश्व समुदाय को अमूल्य उपहार



अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को कोलकाता की ऐतिहासिक रेडरोड पर जनता के साथ योग करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी । एएनआइ

पीएम ने 40 मिनट के सत्र में प्रशिक्षक की भूमिका भी निभाई

बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में पहली बार आयोजित योग दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री ने रेड रोड पर करीब 35,000 लोगों संग योगाभ्यास किया। सफेद टी-शर्ट व पैट पहने मोदी 40 मिनट के सत्र के दौरान प्रशिक्षक की भूमिका में प्रतिभागियों के बीच घूम-घूमकर योगासन सिखाते, मुद्राएं सुधारते व लोगों का मार्गदर्शन करते भी दिखे। इस वर्ष की थीम 'बढ़ती उम्र में योग से रहें निरोग' का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, लोगों का लक्ष्य उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होना नहीं बल्कि अधिक सक्रिय व सक्षम होना चाहिए। 70 की उम्र में भी व्यक्ति 50 जैसा सक्रिय दिख सकता है। योग इसमें सबसे बड़ा सहायक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 20 साल की उम्र की तुलना में 40 साल में

अधिक लचीले हों, 30 की तुलना में 50 में अधिक ऊर्जावान हों। 70 की उम्र में भी बीमारियों से लड़ सकें। कहा, योग को सिर्फ एक दिन या विशेष अवसर तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन, परिवार व आने वाली पीढ़ियों की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पीएम के साथ राज्यपाल आरएन रवि व सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी योगाभ्यास किया। विशेष बात रही कि बंगाल ने 12 वर्षों में पहली बार योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी की। स्कूलों, कालेजों व सार्वजनिक स्थलों पर योग सत्र में लाखों लोग शामिल हुए। हुगली नदी में 500 नावों पर सामूहिक योग किया गया।

योग दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत की अनमोल देन

पेज>>5

चढ़ावा चोरी मामले में एसआइटी जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन की संस्तुति

जागरण संवाददाता, अयोध्या

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआइटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार, एसआइटी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी। अभी तक की जांच में ट्रस्ट महासचिव चंपतराय, सदस्य डा. अनिल मिश्र, व्यवस्थापक गोपाल राव, व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव टिन्नु सहित 14 लोगों पर आंच आ सकती है। एसआइटी ने रिपोर्ट में ट्रस्ट का पुनर्गठन करने समेत कई महत्वपूर्ण संस्तुतियों की हैं।

चढ़ावा प्रकरण सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित एसआइटी ने गत सोमवार को जांच शुरू की थी। चंपतराय व गोपाल राव से व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर जांच आगे बढ़ाई। नकदी की गणना व मंदिर व्यवस्था से जुड़े डेढ़ सौ लोगों के बयान दर्ज किए। ट्रस्टी डा. अनिल मिश्र के बयान का रामशंकर यादव टिन्नु से मिलान किया। असमानता मिलने पर तीन दिन तक दोनों से पूछताछ हुई। संदिग्ध पाए गए अनुकरूप मिश्र, लवकुश मिश्र, मनौष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर, अविनाश शुक्ल, कृष्णदेव तिवारी, सुभाष श्रीवास्तव सहित ट्रस्ट व बैंक से जुड़े 14 लोगों के लिखित बयान दर्ज किए। जांच में कई खामियां मिलीं। पता चला कि सेवादारों को गबन की जानकारी पहले से थी।

रविवार को एसआइटी द्वारा जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपि जाने की चर्चा रही, पर सरकारी प्रवक्ता के अनुसार एसआइटी के अधिकारियों ने रविवार को मुख्यमंत्री से न तो बैठ की और न ही रिपोर्ट सौंपी है।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आज सौंपी जा सकती है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट

ट्रस्टी चंपतराय, डा. अनिल मिश्र, गोपाल राव सहित 14 पर आ सकती है आंच



राम मंदिर ।

फाइल

एसआइटी ने की ये संस्तुतियां

- राम मंदिर ट्रस्ट का हो पुनर्गठन, सभी सदस्यों की तय हो समान जिम्मेदारी
- मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया जाए
- मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल को और समय दिया जाए
- मंदिर के ओर बेहतर प्रबंधन के लिए पेशेवर तरीका अपनाने की सलाह
- दानराशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट किया जाए
- चढ़ावे में आने वाली नकदी की प्रतिदिन इंट्री की व्यवस्था की जाए
- सीसी कैमरों का डाटा स्टोरेज 45 दिन से बढ़ा कर 180 दिन तक किया जाए
- चंपतराय, डा. अनिल मिश्र व गोपाल राव सहित अन्य जिम्मेदारों को अयोध्या छोड़ने की अनुमति न दी जाए

जागरण विशेष

उर्वरक आयात घटने के साथ बढ़ेगी फसलों की उत्पादकता

नोट्स : राजस्थान के थार मरुस्थल में उमने वाले खेजड़ी के पौधे की जड़ों में पाई जाने वाली विशेष फफूंद (फंगस) से विकसित की गई रूटोनिक तकनीक किसानों के लिए नई उम्मीद जगा रही है।

● पेज-6

संपादकीय

जन विश्वास से सुगम होवा जीवन : सुचारू की प्रक्रिया के पीछे प्रधानमंत्री का यही दृष्टिकोण है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक काल के तौर-तरीकों से पूरी नहीं होंगी।

प्रीतूष गोयल का आलेख।

पहले इंसान, फिर वाहन : पैदल चलने वालों के अधिकारों को मान्यता देकर अवलत ने अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी है, अब सरकारों की बारी है।

अमरपाल सिंह वर्मा का दृष्टिकोण।

● पेज-8

विमर्श

होर्मुज संकट से निपटने की रणनीति : होर्मुज जल मार्ग से ऊजड़ी की निबीह आपूर्ति को लेकर आशंका और अनिश्चितता के बादल अभी पूरी तरह से छटे नहीं हैं।

श्री राम शा का आलेख।

सहू पर फूट रहे अंतर्धारा के सोरे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर राजा सुहेलदेव राजभर एवं राजा बिजली शासी जैसी विभूतियों पर नाटक धियार किए जा रहे हैं, जिनका मंचन प्रदेश के सभी जिलों में किया जाना है।

अजय शुक्ला की उत्तर प्रदेश डायरी।

● पेज-9

सप्तर्षि

साहित्य और संगीत का

राष्ट्रधर्मी युगांतकारी रचनाकार

सरों का वशीकरण मंत्र था उनका गायन

● पेज-13

सख्ती का असर

दैनिक जागरण ने अवैध कटों पर हो रहे हादसों में मौतों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, इसके बाद जागा प्राधिकरण, पुलिस ने अवैध कटों पर हादसा होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों पर केस दर्ज कराने के दिए थे आदेश

एफआइआर की चेतावनी पर एनएचएआइ ने बंद किए 50 अवैध कट

नंदकिशोर भारद्वाज • जागरण

सोनीपत : राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर अवैध कट बंद न करने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अफसरों पर केस दर्ज करने की पुलिस की चेतावनी का दो दिन में ही असर दिख गया। एनएचएचआइ ने कुंडली बाईर से पानीपत तक सभी अवैध कट बंद कर दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने दोबारा अवैध कट खोला तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। ज्ञात हो, दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को 18 जून के संस्करण में प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद डीसी ने दो दिन में कट बंद करने के आदेश दिए थे।

एनएच-44 सोनीपत का सबसे असुरक्षित हाईवे है। हर माह जिले में सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में से 50 प्रतिशत इसी हाईवे पर होती हैं। फरवरी से जून तक यातायात पुलिस 10 अवैध कटों

उपायुक्त ने दो दिन में एनएच-44 के सभी अवैध कट बंद करने के दिए थे निर्देश, पानीपत से दिल्ली तक बंद किए गए कट



मुख्यल से बहाल्लाद की ओर नांगल खुर्द गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने स्थित अवैध कट । जागरण



एनएचएचआई द्वारा पेट्रोल पंप के सामने बंद किया गया अवैध कट । जागरण

को बंद कराने के लिए एनएचएचआइ को चार बार पत्र लिख चुकी थी, पर अधिकारी सुन ही नहीं रहे थे। गत सप्ताह पुलिस आयुक्त

हाईवे पर अवैध कट से हादसा तो एनएचएचआइ के अफसरों पर होगा केस



एनएचएचआई द्वारा पेट्रोल पंप के सामने बंद किया गया अवैध कट । जागरण

अधिकारी पर केस दर्ज किया जाएगा। दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त नेहा सिंह ने भी एनएचएचआइ को दो दिन में ही सभी अवैध कट बंद करने के आदेश दिए। एनएचएचआइ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुंडली बाईर से पानीपत के सिवाह बस अड्डे तक 50 से अधिक अवैध कट सीमेंट के बैरिकेड रखकर बंद कर दिए। इनमें से अधिकतर कट पेट्रोल पंपों के सामने बनाए गए थे, जबकि कुछ ढाबों व अन्य प्रतिष्ठानों के सामने थे। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट खुलवाने के लिए कई लोग सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कट नहीं खुलने दिए जाएंगे। वहीं, पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने कहा कि अगर किसी ने भी दोबारा अवैध कट खोला तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस व प्रशासन की सख्ती से हाईवे पर हादसों में होने वाली मौतों में कमी आने की उम्मीद है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कहीं से किसी तरह की गड़बड़ी की नहीं मिली सूचना



नई दिल्ली में रविवार को एक नीट-यूजी परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों की सघन जांच करते पुलिसकर्मी । प्रेस

छात्रों को न हो दिक्कत इसलिए मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बिताए 45 मिनट नीट-यूजी के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी छात्रों की सुविधा का ध्यान रखा। हुआ यह कि कोलकाता से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम खत्म करके पीएम रविवार को 1.15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से उन्हें अपने आवास जाना था। हालांकि, यह छात्रों के परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय था। सूत्रों की माने तो पीएम ने इस दौरान तय प्रोटोकाल के चलते लगने वाले ट्रैफिक जाम

छात्रों को दिया गया था 15 मिनट का अतिरिक्त समय : दोबारा हुई परीक्षा में छात्रों को इस बार 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया था। वैसे तो परीक्षा में केंद्र पर पुलिस के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। हर शहर में साइबर कमांडो भी तैनात किए गए थे। हिंदी, अंग्रेजी सहित 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित नीट-यूजी पर शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान ने भी पनी नजर रखी। वह एनटीए मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में पहुंचे और वहां से सीसीटीवी के जरिये परीक्षा पर नजर रखी।

हर छात्र का सखा गया ध्यान : परीक्षा के दौरान एक-एक छात्र का ध्यान रखा गया। परीक्षा में शामिल करीब 10 हजार दिव्यांग छात्रों के साथ ही 81 ऐसे छात्र भी शामिल हुए थे, जिनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। इनमें कोलकाता की एक छात्रा भी थी, जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं एक छात्र ऐसा भी था जो कोमोथेरेपी करवा रहा था। एनटीए ने भी उनके लिए पूरा बंदोबस्त किया और परीक्षा कराई। (एनटीए ने 'टीम भारत' की कोशिशों को सहाय : पेज-6)

फीफा वर्ल्ड कप

22 जून का मैच

अर्जेंटीना 2x8 अस्ट्रिया

स्थान : डलास समय : 10:30 पीएम

23 जून के मैच

फ्रांस 2x8 इराक

स्थान : फिलाडेल्फिया 2:30 एएम

नार्वे 2x8 सेनेगल

स्थान : न्यूयार्क समय : 6:30 एएम

जार्डन 2x8 अल्जीरिया

स्थान : सैन फ्रांसिस्को 8:30 एएम

प्रसारण : युनाइटेड 1 व 2 स्पोर्ट्स, जी5

स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान शांति वार्ता शुरू, ट्रंप ने ईरान को धमकाया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में साढ़े तीन माह तक चले घमासान और लेबनान में अब भी जारी इजरायली हमलों से उभरी तमाम आशंकाओं के बीच रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्नेनस्टाक में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई। वार्ता में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहे हैं। गत बुधवार को 14 बिंदुओं वाले प्रारंभिक समझौता मसौदे पर बनी सहमति के आधार पर अगले 60 दिनों तक तकनीकी पहलुओं पर वार्ता होगी।

उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा,तेहरान लेबनान में हिजबुल्ला को रोके, वरना अमेरिका पूर्वी की भांति ईरान पर तारबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की चेतावनी के बाद रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा। ट्रंप ने होर्मुज को लेकर भी कहा है कि अगर 60 दिनों में ईरान समझौता नहीं होता है तो अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से आने-जाने के कच्चे तेल की कोमर्त में फिर तेजी आ सकती है। वहीं वैश्विक शेयर बाजारों पर भी असर दिख सकता है।

अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थ बने कतर ने रविवार को वार्ता शुरू होने की घोषणा की। हालांकि, स्विट्जरलैंड में केवल रविवार को ही बातचीत प्रस्तावित है। वार्ता में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से संसद स्पीकर एमबी खलीफा अपने प्रतिनिधिर्मंडल का नेतृत्व कर रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेताया, लेबनान में हिजबुल्ला को रोके तेहरान, वर्ना ईरान पर करेंगे हमला



स्विट्जरलैंड के बर्नेनस्टाक रिजार्ट में रविवार को शांति वार्ता से पूर्व ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराफ़ी से मुलाकात करते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, (पीछे दाएं) अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडि वेंस और (मध्य में) सलाहकार जेरेड कुशमर । रायटर

हैं। इस वार्ता की गंभीरता का आकलन इससे किया जा सकता है कि मौके पर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुलरहमान अल थानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर भी मौजूद हैं।

कतर ने बताया शांति वार्ता को रोकेंगे पेज>>11

समुद्र में क्षमता बढ़ाए बिना कोई राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता : मोदी

प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीन युद्धपोतों आइएनएस दूनागिरि, आइएनएस संशोधक व आइएनएस अग्रय को सेना में किया शामिल

कोलकाता में स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीन युद्धपोत सेना के बड़े में शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोई भी राष्ट्र समुद्र में अपनी क्षमता बढ़ाए बिना बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से ही विकास, सुरक्षा और समृद्धि जुड़ी है। जब समुद्र में किसी भी स्थिति से निपटने में कोई सक्षम होता है तो इससे आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव बढ़ता। वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीन युद्धपोतों आइएनएस दूनागिरि, आइएनएस संशोधक व आइएनएस अग्रय को सेना में शामिल किए जाने के अवसर पर रविवार को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान मोदी ने कहा, ये युद्धपोत आत्मनिर्भर, सुरक्षित व विकसित भारत के परिचायक हैं। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डाटा के बिना देश का विकास संभव नहीं है। आने वाले समय में क्रिटिकल मिशनरल्स, डीप सी रिसोर्सेस व नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए



कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर रविवार को आइएनएस दूनागिरि, आइएनएस संशोधक व आइएनएस अग्रय को नौसेना में सम्मिलित किए जाने के अवसर पर (बाएं से) नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेन्द्रु

जिस देश का समुद्र में सामर्थ्य जितना मजबूत होगा, उसका आर्थिक व रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही बढ़ेगा। देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने

और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 जून को 'वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे' के रूप में भी मनाया

जाता है। यह अदृश्य संयोग है कि आज के दिन हमने देश के सबसे उन्नत हाइड्रोग्राफिक जहाज आइएनएस संशोधक का अनावरण किया है।

आने वाले वर्षों में बंगाल वनेगा देश की ब्लू इकोनोमी

इस दौरान पीएम ने बताया कि यह देश के वर्षों में 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत व पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हुई हैं, जबकि वर्तमान में 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणधीन हैं। यह देश की औद्योगिक क्षमता और भविष्य की शक्ति का प्रमाण है। बंगाल आने वाले वर्षों में देश की ब्लू इकोनोमी व सांयुक्तिक निर्माण के मामले में प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है।

ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है दूनागिरि

आइएनएस दूनागिरि अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर प्रणालियों के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस सतह से सतह और सतह से से आकाश तक दूरीमान पर सटीक मार करने की क्षमता रखती है। युद्धपोत पर लगे अत्याधुनिक उपकरण व स्टेलथ तकनीक के कारण यह रडार की पकड़ में नहीं आया।

संशोधक देश का चौथा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत

आइएनएस संशोधक देश का चौथा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इसे तटीय क्षेत्रों व गहरे समुद्री इलाकों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने तथा रक्षा एवं नागरिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने के उद्देश्य से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

दुश्मन की पनडुब्बियों के छत्के छुड़ा देगा अग्रय

आइएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों और अन्य खतरों का मुकाबला करने में इसे बेहद प्रभावी माना जा रहा है। यह टारपीडो, स्वदेशी राकेट लांचर और उथले जल के लिए विकसित सोनार प्रणाली से लैस है, जिससे समुद्र के भीतर से आने वाले किसी भी खतरे का जवाब दिया जा सकेगा।

समुद्री हितों की रक्षा का अभियान होगा और शक्तिशाली नौसेना प्रमुख

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि देश की युद्धपोत निर्माण क्षमता आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास के बल पर नई गति पा रही है। इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समुद्री हितों की रक्षा का अभियान अधिक प्रभावी व शक्तिशाली बनेगा।

'100%' का भ्रामक दावा करने वाली दो कंपनियों पर सीसीपीए ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेड : केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 'स्टोरिया फूड्स एंड बेकवेजेज प्राइवेट लिमिटेड' और 'इंग्लिश ओवन' ब्रेड बनाने वाली कंपनी 'मिसेज बेकटर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड' पर एक- एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने रविवार को कहा कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने उत्पादों को लेकर विज्ञापनों में "100%" का भ्रामक दावा किया। सीसीपीए ने दोनों कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आधिकारिक वेबसाइट और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन दावों को तुरंत हटा दें। सीसीपीए ने कहा, 100% शब्द सटीक और और पूर्ण संख्यात्मक पैमाना है। इसे हल्के-फुल्के ढंग से, अंदाजित या मार्केटिंग स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीसीपीए ने दोनों 'स्टोरिया फूड्स' के उन विज्ञापनों पर खुद संज्ञान लिया जिनमें "100% टेंडर कोकोनट वाटर" (नारियल पानी) और "100% अनार, मिक्स्ट फ्रूट, आम और अमरूद-मिर्च वाले जूस का दावा किया गया था। इन प्रोडक्ट्स का प्रचार कंपनियों को वेबसाइट, प्रोडक्ट पैकेजिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किया गया था। जांच में पता चला कि 100% नारियल पानी का दावा गुमराह करने वाला था। नारियल पानी में प्रिजर्वेटिव्स थे।

पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया 'निर्भय चेतना' कार्यक्रम

देशभर के 17.5 लाख पुरुष सरपंचों को मिलेगी महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग

इनके प्रशिक्षण के लिए 28,500 मास्टर ट्रेनर किए जाएंगे तैयार

माला दीक्षित • जागरण

नई दिल्ली : कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की, जहां पंचायत का सरपंच महिला सुरक्षा को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझता हो। जहां बाई का पंच किसी भी पीड़ित महिला को न केवल थाने तक पहुंचाने में सहयोग करे, बल्कि मुआवजे और कानूनी सहायता की पूरी प्रक्रिया में मदद करे। जहां गांव समा में महिलाओं की बात सुनी जाए, उनके निर्णयों का सम्मान हो। उनकी सुरक्षा को विकास की पहली शर्त माना जाए। यह प्रतीक कल्पना नहीं, पंचायती राज मंत्रालय की सुनिश्चित व सुविचारित पहल है। सरकार का मानना है कि जब प्रधान का सोच बदलता है, तो गांव की तस्वीर बदलती है। इसे साकार करने को सरकार



प्रतीकात्मक

ने तय किया है कि देशभर में पंचायतों के 17.5 लाख से अधिक पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों, लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्यों, महिला अधिकारों व उनकी सुरक्षा व गरिमा के प्रति उत्तरदायित्व संबंधी विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर 28,500 मास्टर ट्रेनर्स तैयार होंगे, जो निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से निर्भया फंड से संचालित होगा। इसका उद्देश्य उन पुरुषों का सोच बदलना है, जिनकी बात गांव सुनता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 में देशभर में महिलाओं के विरुद्ध 4.4 लाख से अधिक अपराध दर्ज हुए, अर्थात् हर घंटे में करीब 50 महिलाएं किसी न किसी अपराध की शिकार हुईं। इनमें 42 प्रतिशत से अधिक केस घरेलू क्रूरता के थे। लिहाजा महिला सुरक्षा को लेकर पंचायती राज मंत्रालय ने इस बार नई पहल की है कि अगर हिंसा का स्रोत पुरुष का सोच में है तो समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपराध के बाद न्याय नहीं, अपराध से पहले रोकथाम की बात करता है।

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया द्वारा विकसित निर्भय चेतना प्रशिक्षण माड्यूल, समावेशी विकास के लिए पंचायतों में पुरुषों की नई परिभाषा देता है जिसमें समूह चर्चा और अनुभव आधारित शिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों का स्वयं से आमना-सामना कराया जाता है। यह प्रशिक्षण एक दर्पण की तरह काम करता है जिसमें यह नहीं बताया जाता

कि आप गलत हैं, बल्कि यह पूछता है कि क्या आप बेहतर हो सकते हैं। निर्भय चेतना अभियान शुरू हो चुका है और पिछले सप्ताह 17 से 19 जून तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम चला। इसमें असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड से 40 मास्टर ट्रेनर्स सम्मिलित हुए। यह पहला बैच था। आने वाले समय में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28,500 मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से 17.5 लाख पुरुष प्रतिनिधियों तक पहुंचा जाएगा।

निर्भय चेतना के साथ ही 'निर्भय नेत्री' के अंतर्गत देशभर की 14.5 लाख महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानूनी साक्षरता और क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे स्थानीय प्रशासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। इसके अलावा 'निर्भय दृष्टि' के माध्यम से पंचायत स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होने को लेकर बन रही उम्मीदों के बीच भारत, ईरान के साथ अपने पारंपरिक ऊर्जा संबंधों को मजबूती देने पर आगे बढ़ रहा है। ईरान की तरफ संकेत है कि वह नए माहौल में भारत के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाने को तत्पर है। यही वजह है कि अगले हफ्ते ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन (गुरुग्राम में) के लिए ईरान अपने पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकेनजाद के नेतृत्व में एक बड़ा दल भेज रहा है। इसमें ईरान सरकार में उप-ऊर्जा मंत्री व कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इनकी भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिजली मंत्री मनोहर लाल से अलग से द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है जिसमें दोनों देशों के बीच तेल एवं गैस खरीद के अलावा ऊर्जा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विमर्श होने की संभावना है।

माना जा रहा है कि ईरान सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष की समाप्ति के बाद जल्द से जल्द अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल व गैस की खुलकर बिक्री करने की तैयारी में है। अभी उसका सबसे बड़ा खरीदार देश चीन है। अमेरिकी

ईरान के पेट्रोलियम मंत्री पाकेनजाद और आ ऊर्जा मंत्री आ रहे भारत

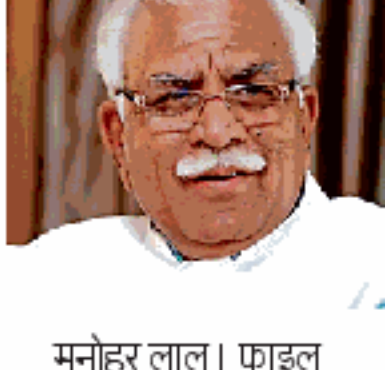
ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में रूसी पेट्रोलियम मंत्री भी होंगे शामिल



मोहसिन पाकेनजाद।



हरदीप सिंह पुरी।



मनोहर लाल। फाइल

प्रतिबंध की वजह से भारत, ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुका है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भारत, चीन के बाद तेल व गैस का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। माना जा रहा है कि कच्चे तेल की खरीद में भारत, चीन को भी पीछे छोड़ देगा। यूरोप, जापान जैसे अन्य कच्चे तेल के खरीदार देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने से कच्चे तेल की खरीद कम होने वाली है। ऐसे में ईरान के लिए भारत एक प्रमुख तेल क्रेता देश होगा। भारत दशकों तक ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता रहा है। भारत की कई रिफाइनरियों को ईरान के तेल के लिए बेहद उपयुक्त भी माना जाता है। अब दोनों पक्षों को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की समाप्ति का इंतजार है।

अधिकारियों का कहना है कि 25-26 जून, 2026 को गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की होने वाली बैठक वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए काफी अहम होगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा तक सभी देशों की पहुंच (खरीद) व ऊर्जा क्षेत्र में समानता जैसे विषयों पर गहन विमर्श होगा। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया भर के देश ऊर्जा सुरक्षा, किफायती मूल्य और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और दुनिया भर की बढ़ती मांग की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत ब्रिक्स संगठन के ऊर्जा एजेंडा को काफी महत्व देता है क्योंकि इसके तीन प्रमुख देश (रूस, ईरान व यूएई) भारत के सबसे बड़े ऊर्जा सहयोगी देश रहे हैं।

बंगाल के लिए 60 हजार करोड़ रुपये के आवंटन की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी नव निर्वाचित भाजपा सरकार

पीएम ने शुभेदु को लिखे पत्र में विकास के लिए केंद्र के सहयोग का इशारा भेरासा

रुपये का आवंटन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा, जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां किसानों को नीति निर्धारण के केंद्र में रखा जाता है और उन्हें विश्वास है कि बंगाल भी इसका अपवाद नहीं होगा। पीएम कहा कि बंगाल में मत्स्य पालन, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, बंदरगाह, आधुनिक विकास, वस्त्र उद्योग, पर्यटन तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति उसे व्यापार और संपर्क का प्रमुख प्रवेश द्वार बना सकती है।

आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी नव निर्वाचित भाजपा सरकार

पीएम ने शुभेदु को लिखे पत्र में विकास के लिए केंद्र के सहयोग का इशारा भेरासा

रुपये का आवंटन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा, जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां किसानों को नीति निर्धारण के केंद्र में रखा जाता है और उन्हें विश्वास है कि बंगाल भी इसका अपवाद नहीं होगा। पीएम कहा कि बंगाल में मत्स्य पालन, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, बंदरगाह, आधुनिक विकास, वस्त्र उद्योग, पर्यटन तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति उसे व्यापार और संपर्क का प्रमुख प्रवेश द्वार बना सकती है।

डोभाल-वांग यी के बीच सीमा विवाद पर होगी बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत के वैदिकसीय दौरे पर आ रहे हैं। वह ब्रिक्स देशों के एनएसए की 16वां बैठक में भाग लेंगे, पर इस यात्रा का सबसे अहम पहलू भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता माना जा रहा है। इस बैठक में भारत-चीन सीमा विवाद और सीमा पर शांति-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। वांग यी व अजीत डोभाल दोनों भारत-चीन सीमा विवाद व मुद्दामें के लिए एक-दूसरे की जाने वाली वार्ता में विशेष प्रतिनिधि हैं। इनकी अनुमति में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। हालांकि, खास प्रगति नहीं हुई है। इनके बीच सबसे हालिया बैठक (24वें दौरे की) अगस्त 2025 में दिल्ली में हुई थी।



अजीत डोभाल। फाइल

आज भारत के वैदिकसीय दौरे पर आ रहे हैं चीन के विदेश मंत्री



वांग यी। फाइल

विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की शुरुआत करने का फैसला जून, 2003 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान हुआ था। तब कहा गया था कि सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता से निकाला जाएगा, पर सीमा विवाद का अंतिम समाधान या

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) के निर्धारण पर भी खास प्रगति नहीं हुई है। उल्टे विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बावजूद दोनों देशों के बीच रह-रहकर सीमा पर सैन्य तनाव पैदा हो जाते हैं। भारत का मानना है कि चीन स्थायी समाधान के प्रति गंभीर नहीं है और वह एलएससी को बदलने की लगातार कोशिश

करता है। दूसरी तरफ, चीन कहता है कि हमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को पुराने नजरिए से नहीं देखना चाहिए। चीन पैकेज समाधान की भी बात करता रहा है, पर मामले में ठोस प्रगति नहीं दिखाई देती है। अगस्त, 2025 की वार्ता में भी दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई थी।

भारत-चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवन घाटी में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच गतिरोध गहरा गया था। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद 2024 के अंत में डेपसॉंग और डेमचोक क्षेत्रों में काफी हद तक सैन्य वापसी हो चुकी है और सीमा पर अपेक्षाकृत शांति है। लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं है कि दोनों देशों के

बीच सीमा विवाद के पूर्ण समाधान को लेकर कोई व्यवस्था बन पाई है। भारतीय पक्ष का स्पष्ट रुख है कि जब तक सीमा पर पूरी तरह से शांति व स्थिरता स्थापित नहीं हो जाती। विस्थापन के बाकी मुद्दों का समाधान नहीं निकलता, तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

वांग यी की यात्रा मुख्य रूप से ब्रिक्स के एनएसए की बैठक के लिए है, जो भारत की अध्यक्षता में 22-23 जून को नई दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के एनएसए वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा व सिलेंडर में होने वाले ब्रिक्स रिस्कर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस मंच का प्रयोग वह बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ द्विपक्षीय मुद्दों के हल के लिए कर रहा है।

केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को तीन साल के लिए फिर सालिसिटर जनरल नियुक्त किया

नई दिल्ली, आइएनएस : केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को अगले तीन साल के लिए फिर से भारत का सालिसिटर जनरल नियुक्त किया है। यह नियुक्ति एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुषार मेहता की पुनः नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सालिसिटर जनरल पद पर तुषार मेहता की तीसरी बार पुनर्नियुक्ति की गई है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के तौर पर काम करने के बाद, मेहता को अक्टूबर 2018 में सालिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 2020 और 2023 में भी बढ़ाया गया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नीतिगत और आपराधिक मामलों में केंद्र सरकार का

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी नियुक्ति को मंजूरी



तुषार मेहता। फाइल

इससे पहले दो बार बढ़ाया जा चुका है कार्यकाल

प्रतिनिधित्व किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) की तीन साल के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। विक्रमजीत बनर्जी और केएम. नटराज की पुनर्नियुक्ति एक जुलाई से जबकि एसबी. राजू, एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी की पुनर्नियुक्ति 30 जून, 2026 से प्रभावी होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एएसजी वरुण शर्मा की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी : एक अन्य निर्णय में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल एक जुलाई, 2026 से छह माह के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

सिर्फ शुल्क प्रतिपूर्ति से आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे निजी स्कूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

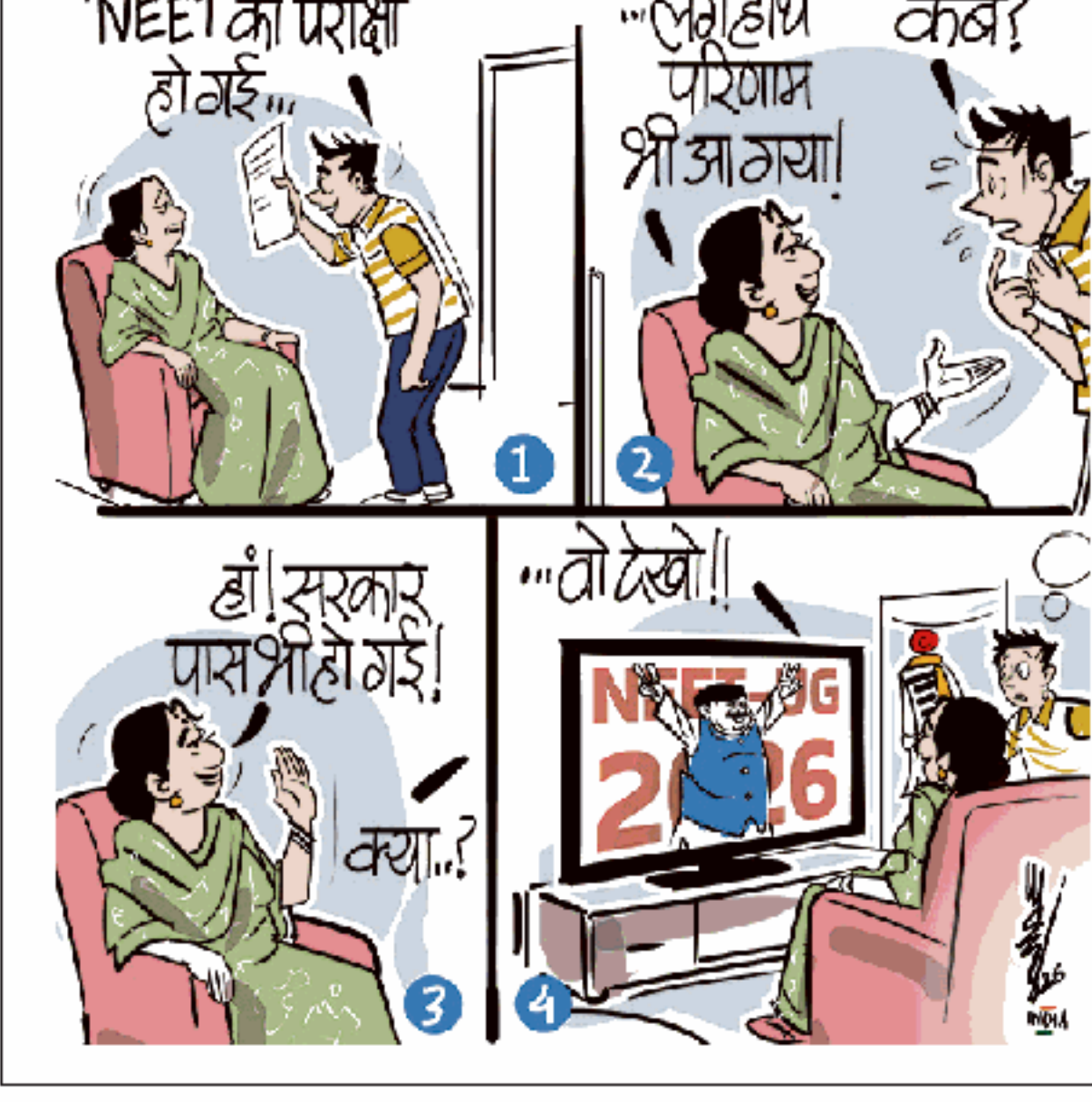
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े मामले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ शुल्क प्रतिपूर्ति या सरकारी उपक्रम के साथ वित्तीय व्यवस्था होने मात्र से कोई निजी स्कूल सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं बन जाता। कहा, किसी निजी स्कूल को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए उस पर सरकारी का व्यापक नियंत्रण या पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण होना जरूरी है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने यह फैसला कोरबा स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। स्कूल प्रबंधन ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संस्था को सार्वजनिक प्राधिकरण मानते हुए उसके

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीआइसी का आदेश किया निरस्त,

कहा- संस्था पर सरकार का गहरा व व्यापक नियंत्रण जरूरी

प्राचार्य को 'डीमंड पब्लिक इंफार्मेशन आफिसर' घोषित किया गया था और सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मामला एक पूर्व कर्मी की सेवा समाप्ति के बाद शुरू हुआ था। कर्मी के स्वजन ने आरटीआई के तहत स्कूल के प्रशासनिक व सेवा संबंधी मामलों की जानकारी मांगी थी। हाई कोर्ट ने पाया कि दक्षिण पूर्वी कोलपील्ड्स लिमिटेड के साथ स्कूल की व्यवस्था सिर्फ कर्मियों के बच्चों को रियायती शिक्षा मुहैया कराने व उससे होने वाले छात्रों की भरपाई तक सीमित है। इसे 'पर्याप्त वित्तीय सहायता' नहीं माना जा सकता।

कह कर रहेंगे माधव जोशी



के लिए पहुंचते हैं। हरकी पैड़ी सहित हरिद्वार के प्रमुख घाटों पर जल पुलिस के गोताखोर तैनात रहते हैं। लेकिन उत्तरी हरिद्वार के गंगा घाटों पर न जल पुलिस तैनात है और न श्रद्धालुओं को खतरे वाली जगहों पर जाने से रोकने की कोई व्यवस्था है। कुछ घाटों पर चेतावनी बोर्ड जरूर लगे हैं।

नेट सेवाएं तलवारें लहराने
मे नक नंन पिंया गफ्फाये ने

ट्रेन में फर्जी ई-टिकट के साथ यात्रा कर रहे यात्री भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, बस्ती : फर्जी ई-टिकट पर मुंबई की यात्रा कर रहे चार यात्रियों को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि दलाल ने दूसरे लोगों के नाम पर पहले से बुक टिकटों में नाम और आधार कार्ड के व्यक्ति को डीएम फेरबदल कर उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया था। मुंबई के कथित टिकट दलाल अखर जहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फर्जी आधार कार्ड, ई-टिकट, चैट और धुतान से जुड़े प्रमाण भी जब्त कर लिए गए हैं।

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त लखनऊ और सहायक सुरक्षा आयुक्त गोरखपुर की टीम को सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 22537 कुशीनगर एक्सप्रेस में कुछ यात्री फर्जी टिकट पर सफर कर रहे हैं। शनिवार रात नौ बजे बभनान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एस-3 कोच की जांच में बर्ध संख्या 25, 26, 27 और 30 पर यात्रा कर रहे अद्वुल हकीम, अनिश अहमद, अफसाना खातून व सलीममल्लाह को पकड़ गया।

स्वदेशी सैन्य शक्ति

प्रधानमंत्री ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर जिन तीन नौसैनिक जहाजों आइएनएस दुनागिरि, आइएनएस संशोधक और आइएनएस अग्रय का शुभारंभ किया, उनकी विशेषता यह है कि वे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हैं। निःसंदेह यह एक उपलब्धि है और इस बात को रेखांकित करती है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में अब केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आवश्यकता की अधिकाधिक रक्षा सामग्री का उत्पादन देश में ही करना होगा। यह इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान में किसी भी देश की सैन्य शक्ति का आकलन केवल इससे नहीं किया जाता कि उसके पास कैसे और कितने हथियार हैं, बल्कि इससे अधिक किया जाता है कि वह अपने स्तर पर रक्षा सामग्री का कितना अधिक निर्माण करता है? यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसके दायरे में रक्षा सामग्री अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। यह ठीक नहीं कि भारत अभी भी रक्षा सामग्री के एक प्रमुख आयातक देश के रूप में जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेश निर्मित युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की गई हैं। एक समय ऐसा था जब भारत अपनी हर छोटी-बड़ी रक्षा सामग्री का आयात करता था। इससे रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती थीं।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग एक दशक में रक्षा सामग्री के स्वदेश में निर्माण को बल मिला है। इसके चलते देश में रक्षा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जहां 2014 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन 40 हजार करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भरता को रेखांकित तो करता है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना शेष है। कुछ समय पहले तक भारत में ज्यादातर रक्षा सामग्री का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में होता था। इसके चलते रक्षा सामग्री के उत्पादन की गति धीमी थी और उन्नत रक्षा सामग्री का निर्माण भी नहीं हो पाता था। यह अच्छा हुआ कि रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी क्षेत्र का भी योगदान लेना शुरू किया गया। इसका परिणाम यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ा है और वर्तमान में यह 38 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। अब भारतीय रक्षा उत्पाद विश्व के करीब 80 देशों में निर्यात किए जाते हैं। यह ठीक है कि 2029 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश में रक्षा सामग्री के उत्पादन की कई परियोजनाएं लंबित चल रही हैं। इनके कारणों की पहचान कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाना चाहिए।

पर्यटन प्रबंधन

यह अच्छा है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक संख्या बढ़ रही है और मैदानों की गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। यह और बात है कि मानसून अभी प्रसन्न नहीं हुआ है और हिमाचल प्रदेश के कतिपय क्षेत्र उतने ठंडे नहीं रह गए हैं, जितने समझे जाते हैं। इसके बावजूद, हरियाली और ठंडक अभी तक हिमाचल प्रदेश की परंपरागत विशेषताओं में सम्मिलित हैं। हिमाचल प्रदेश की ये विशेषताएं बचो रहें, इसके लिए उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करना समय की मांग है। हिमाचल प्रदेश में कतिपय कारणों से लगातार बनती जाम की स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। इस बहस में गए बिना कि पर्यटन से हिमाचल प्रदेश कितनी कमाई कर रहा है, यह देखना बहुत आवश्यक है कि कतिपय कारणों से कहीं नकारात्मक छवि तो नहीं बन रही। भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन एक पक्ष है, लेकिन सड़कों की स्थिति और पर्यटकों और कुछ स्थानीय लोगों का व्यवहार ऐसे कारक हैं जिन पर विस्तृत विमर्श होना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर फैलता कचरा तो स्थूल प्रदूषण है, किंतु अब सांस्कृतिक प्रदूषण भी ऐसा रोग है जिसका उपचार आरंभ करना आवश्यक प्रतीत होता है। सफेद बर्फ पर प्लास्टिक कचरा और वाहनों से निकलती कार्लिध हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार से सफेद नहीं कर सकती। साहसिक पर्यटन के नाम पर गैर पंजीकृत गतिविधियों से होने वाला तात्कालिक लाभ दूरगामी हानि में बदल सकता है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े प्रत्येक पक्ष को विचार करना चाहिए कि पर्यटन प्रबंधन कैसे हो।

दवाओं की सुरक्षा से खिलवाड़

सुभाष बुधमन वाला

स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जब दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। केंद्र सरकार ने हाल में 16 ऐसी फिक्स्ड डोज़ कार्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाया है, जिनमें दो या अधिक औषधियों को मिलाकर तैयार किया जाता था। सरकार का कहना है कि इन दवाओं के उपयोग का पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं मिला और इनके लंबे समय तक सेवन से नुकसान की आशंका थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि ये दवाएं जनस्वास्थ्य के लिए उचित नहीं थीं, तो इन्हें वर्षों तक बाजार में आने की अनुमति कैसे मिलती रही? दवाओं को मंजूरी देने वाली व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कोई भी दवा बाजार में आने से पहले कठोर

एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए जरूरी है कि दवाएं मरोसे का माध्यम बनें, व्यापार का साधन नहीं

वैज्ञानिक परीक्षणों और सुरक्षा मानकों से गुजरे। इससे यह संकेत मिलता है कि देश को दवा नियामक व्यवस्था में लगातार निगरानी और समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि किसी दवा की उपयोगिता और सुरक्षा वर्षों बाद जांची जाती है, तो यह व्यवस्था को कमजोर को दर्शाता है। विकसित देशों में नई जानकारी सामने आते ही दवाओं की समीक्षा कर ली जाती है, लेकिन भारत में कई बार ऐसी दवाओं पर कार्रवाई देर से होती है। इसे देश का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सलाह के अभाव में लोग आसानी से उपलब्ध दवाओं का उपयोग कर लेते हैं। एक और गंभीर समस्या दवाओं के विज्ञापनों की है। कई बार आकर्षक प्रचार के माध्यम से लोगों को ऐसी दवाएं लेने के लिए प्रेरित किया जाता



पियूष गोयल

सुधारों की प्रक्रिया के पीछे प्रधानमंत्री का यही दृष्टिकोण है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक काल के तौर-तरीकों से पूरी नहीं होंगी

भारत की नियामकीय प्रणाली

हमेशा दुविधा की मानसिकता के साथ काम करती थी और अक्सर छोटी प्रक्रियागत त्रुटियों या केवल आरोपों के कारण नागरिकों को कड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ते थे। मोदी सरकार ने प्रत्येक नागरिक के लिए विश्वास, सहानुभूति और सम्मान में निहित शासन को बढ़ावा देते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों और व्यवसायों का समर्थन करने, अनुपालन को अदल बनाने और व्यवसायों के समक्ष व्यावहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे अनुपालन बोझ घटाना हो, डिजिटलीकरण बढ़ाना हो, या एकल-खिड़की मंजूरी हो, कुल मिलाकर बदलाव का मकसद शासन के अदल बनाने और कुशल बनाना रहा है।

प्रधानमंत्री का विश्वास और सहानुभूति पर आधारित शासन का मंत्र स्पष्ट रूप से जन विश्वास अधिनियम, 2026 और 2023 के इसी तरह के एक कानून में दिखाई देता है। नागरिक-अनुकूल नियामकीय परिवेश बनाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नया कानून मामूली अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट सिद्धांत अपनाता है: दंड से

पहले चेतावनी देना, अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना तय करना, त्वरित एवं पारदर्शी समाधान और जुर्माने का एक गतिशील ढांचा, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता हो, ताकि नियम लागू करने का तरीका प्रभावी, प्रारंभिक और समय के साथ उन्नतवादी बना रहे। यह दृष्टिकोण, अनुपालन और प्रवर्तन के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जो प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं औपनिवेशिक शासन के पुराने तरीकों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकतीं।

इस सुधार का पैमाना अभूतपूर्व है। जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रविधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए 717 प्रविधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रविधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है। यह 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है। पुराने अप्रचलित अपराधों को समाप्त कर अपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है। पूर्व की व्यवस्था में किसी घर, इमारत या वाहन में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच उपस्थिति को लेकर संतोषजनक जवाब न देने पर

पहले इंसान, फिर वाहन

देश की सर्वोच्च अदालत ने हाल में एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि विकास को लेकर हमारे सोच पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सड़कों पर पैदल चलने वालों का अधिकार मोटर वाहनों से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह कहा है कि इंसान ने पहिए आने से बहुत पहले चलना सीख लिया था। यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं, बल्कि हमारी शहरी और ग्रामीण विकास नीतियों पर एक गहरी टिप्पणी भी है। यह फैसला एक दर्दनाक हादसे की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें एक पिता ने अपने पांच साल के बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया था। अदालत ने इस मामले को केवल मुआवजे तक सीमित नहीं रखा, कोर्ट ने पैदल चलने वालों के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से जोड़कर उसे मौलिक अधिकार का दर्जा भी दे दिया। कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों महत्वपूर्ण और दूरगामी है, इसके लिए कुछ बातों पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल, पिछले कुछ दशकों में देश का विकास लगभग पूरी तरह वाहनों के इर्दगिर्द केंद्रित रहा है। शहरों में फ्लाईओवर बने, चौड़ी सड़कें बनीं, एक्सप्रेसवे बने, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपार्थों की जरूरत को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। विर्दबना यह है कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी पैदल चलकर ही अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करती है। गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग और छोटे कस्बों के लोग सबसे ज्यादा पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन सड़कें मानो केवल वाहनों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अदालत का यह कहना पूरी तरह सही है कि शुरुआत में यह एक तरह का 'आभिजात्य प्रभाव' था। जब वाहन केवल अमीरों के पास थे, तब भी पैदल चलने वालों को महत्व नहीं मिला और जैसे-जैसे वाहन सस्ते हुए, पूरी सड़क पर वाहनों का कब्जा हो



अमरपाल सिंह वर्मा



फुटपाथ को रखना होगा अतिक्रमण से मुक्त।

फाइल

गया। आज स्थिति यह है कि कई शहरों में फुटपाथ हैं ही नहीं और जहां हैं, वहां दुकानों, ठेलों, पार्किंग और अतिक्रमणों ने उन्हें निगल लिया है।

इस निर्णय में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश है। यह निर्णय नागरिकों के लिए पैदल चलने के अधिकार को स्थापित करता है। अब फुटपाथ कोई सरकारी दया का विषय नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार का प्रश्न है। इसके साथ-साथ अदालत ने नगर निर्माण, विकास प्राधिकरणों, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी तय की है। अब वे यह कहकर नहीं बच सकते कि संसाधन नहीं हैं या यह उनकी प्राथमिकता नहीं है। अगर सड़क है तो फुटपाथ भी होना चाहिए। इस फैसले से नागरिकों को कानूनी अधिकार मिला है कि यदि फुटपाथ नहीं हैं, टूटे हुए हैं या उन पर कब्जा है तो वे अदालती दख्खाना खटखटा सकते हैं और हजाने की मांग भी कर सकते हैं। अगर इस फैसले को धरातल पर लागू किया जाता है तो इसके दूरगामी लाभ होंगे। सड़क दुर्घटनाओं में

बड़ी कमी आएगी। आवाजाही सुगम होगी। प्रदूषण कम करने और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि सरकारें इस फैसले को कितनी गंभीरता से लेंगी? आज देश के अधिकांश छोटे शहरों और कस्बों में फुटपाथ नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां फुटपाथ बने भी हैं, वे दुकानों के आगे बड़े चबूतरों, पार्किंग, सामान रखने के स्थानों और अस्थायी कब्जों में बदल चुके हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब नगर निकाय फुटपार्थों से अतिक्रमण हटाएंगे? क्या नई सड़क परियोजनाओं में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी?

विभिन्न अदालतों ने समय-समय पर जनहित में फैसले किए हैं, पर उनका क्रियान्वयन कितना हुआ है, इसे देखे जाने की जरूरत है। फुटपार्थों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब प्रत्येक शहर और कस्बे में फुटपार्थों का सर्वे कराया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। नई सड़क परियोजनाओं में फुटपाथ अनिवार्य किए जाने चाहिए। स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों के आसपास पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित पैदल मार्गों की योजना बनाई जाए। यह सब जरूरी है, क्योंकि किसी सभ्य समाज की पहचान उसकी चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवरों और एक्सप्रेसवे से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वहां सबसे कमजोर और असुरक्षित व्यक्ति कितनी सुरक्षा और सम्मान के साथ चल सकता है। जब पैदल चलने वाला नागरिक सुरक्षित होगा, तभी हम अपने विकास को सचमुच मानवीय विकास कह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और एक स्पष्ट संवैधानिक दिशा दे दी है। अब गैद कार्यपालिका के पाले में है। देखना यह है कि सरकारों इस ऐतिहासिक फैसले को केवल न्यायालय के पन्नों तक सीमित रहने देती हैं या उसे वास्तविकता का स्वरूप देकर साकार करती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। response@jagran.com)



अवधेश राजपूत

किसी व्यक्ति को तीन महौने तक की जेल हो सकती थी।

औपनिवेशिक काल में सामान्य आवाजाही की संदेह की दृष्टि से देखे जाने वाले इस प्रविधान को समाप्त कर दिया गया है। पहले किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की समयसीमा समाप्त होने के तुरंत बाद गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर उसे अपराध की दृष्टि से देखा जाता था। नए कानून में इस मोर्चे पर 30 दिन की छूट अर्वाध दी गई है। इसी क्रम में अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण अद्यतन न कर पाना पहले आपराधिक कृत्य था, पर अब केवल नियमों की बार-बार अवहेलना पर ही सख्त कार्रवाई होगी। पहले किसी खनन कंपनी को दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में चूक के कारण जेल तक हो सकती थी, लेकिन अब जुर्माना ही पर्याप्त है।

इस संदर्भ में जन विश्वास कानून वस्तुतः समस्त नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के पीएम मोदी के प्रयासों का ही प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर देश-सेवा के 12 वर्षों में और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर

यह उनका प्रमुख मिशन रहा है। जन विश्वास, 2026 एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित है। भारत ने 2023 में पहले जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 42 अधिनियमों के 183 प्रविधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस प्रयास ने दिखाया कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को कमजोर किए बिना गैर-अपराधीकरण से शासन में सुधार संभव है। 2026 का कानून इस प्रक्रिया को लगभग चार गुना बढ़ाता है, जो यह संकेत है कि यह कोई एक बार की गई पहल नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समग्रता में देखें तो कम गंभीरता वाले आपराधिक प्रविधानों की जगह प्रशासनिक और मौद्रिक व्यवस्थाएं लाना, न सिर्फ आम नागरिक के लिए स्वागतयोग्य है, बल्कि छोटे व्यवसायों की भी मदद करता है। इससे प्रवर्तन एजेंसियां भी रोजमर्रा की तकनीकी गलतियों के बजाय गंभीर उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

नियमों में सुगमता के लाभ अर्थव्यवस्था और निवेश के मोर्चे पर भी



ऊर्जा

विचार और वाणी

मानव जीवन में विचार और वाणी दो महत्वपूर्ण घटक हैं। मनुष्य के अनुभव, ज्ञान और भावनाओं से उत्पन्न विचार वाणी को माध्यम बनकर स्वयं को आकार देते हैं। वैचारिक उत्कृष्टता जितनी समृद्ध होगी, वाणी भी उतनी प्रभावी होगी। वाणी विचारों का ही अनुसरण करती है। इसलिए वाणी को विचारों का प्रतिबिंब कहना उचित होगा। जिस प्रकार अच्छी पुस्तकों का अध्ययन श्रेष्ठ विचारों का पोषक माना गया है, उसी प्रकार मन, बुद्धि और ज्ञान की छलनी से छनकर व्यक्त की जाने वाली वाणी को अंतस की आवाज समझा गया है।

वैचारिक शुद्धता और वाणी चातुर्य का मिश्रित रसायन ही मनुष्य की सफलता का आधार है, जो उसके मानसिक और वाचिक तप का प्रतिफल होता है। मानसिक तप से जैसे वैचारिक स्वच्छंदता को नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही वाचिक तप से वाणी को कटुता रूपी अर्थ का निमित्त बनने से रोक जा सकता है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता मानसिक तप है तो दूसरों को विचलित नहीं करने वाला मृदुभाष्य सत्यकथन और संवेदनशीलता वाचिक तप है। दोनों की साधना से मन की मालिनता का शमन होते रहने से मनुष्य के मन में न केवल श्रेष्ठ विचारों का प्रस्फुटन होने लगता है, वरन वह जैसा सोचता है वैसा ही बोलना भी आरंभ कर देता है। मानसिक विचार और वाणी का यह तादात्म्य उसकी वाक्पटुता की श्रेष्ठता को स्थापित कर उसे दूसरों के लिए प्रेरक बनाता है।

यू तो मनुष्य की साधारण पहचान उसके चेहरे से होती है, किंतु उसकी समग्र एवं व्यापक पहचान उसके विचारों और वाणी से ही होती है। वैचारिक उत्कृष्टता के साथ वाणी का स्तर जिस मनुष्य का जितना श्रेष्ठ होगा, वह उतना ही आकर्षक और सर्वप्रिय होगा।

एसएन दुवे 'स्नेही'

लैस है। दूसरे नैसैनिक पोत का नाम आइएनएस संशोधक (जे-17) है। यह सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) श्रेणी का पोत है। यह समुद्र की गहराइं मापने, नौवहन चार्ट तैयार करने तथा पनडुब्बियों के लिए सुरक्षित मार्ग खोजने का कार्य करता है। इसे 'समुद्र का डाक्टर' भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह जीपीएस के बिना भी समुद्री मानचित्र तैयार करने में सक्षम है। तीसरा कमीशन किया गया पोत आइएनएस अग्रय (जे-16) है। यह भी सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का पोत है। 'अग्रय' का अर्थ है- 'आगे बढ़ने वाला'। यह समुद्री हाइड्रोग्राफी का कार्य करेगा, बंदरगाहों के मानचित्र तैयार करेगा तथा समुद्री प्रदूषण की निगरानी करेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह युद्धकाल में पनडुब्बी-रोधी अभियानों में भी संयोजित करेगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में जहां सैन्य शक्ति का निरंतर विस्तार हुआ है, वहीं भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से बढ़ रहा है।

धर्मद नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकाण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,

डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा

ई-मेल: response@jagran.com



श्री राम शा

shriramshaw
@nda.jagran.
com

आजकल

होर्मुज संकट से निपटने की रणनीति

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर 'सहमति' बनना पश्चिम एशिया के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर तो हो सकती है, लेकिन होर्मुज जल मार्ग से ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को लेकर आशंका और अनिश्चितता के बादल अभी पूरी तरह से छटे नहीं हैं। क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जल मार्ग में आपूर्ति बाधित रहने की आशंका को भारत के लिए केवल एक बाहरी संकट नहीं, बल्कि एक 'रणनीतिक चेतावनी' माना जाना चाहिए।

पश्चिम एशिया का संकट दक्षिण एशिया की खुशहाली के लिए एक आर्थिक खतरा बन चुका है। हालांकि यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता आर्थिक क्षेत्र है, पर विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि ईंधन, गैस और उर्वरकों की बढ़ती कीमतें इसे सबसे अधिक प्रभावित कर सकती हैं। संकट के इस प्रभाव के कारण दक्षिण एशिया की आर्थिक विकास दर साल 2025 के सात प्रतिशत से घटकर 2026 में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तमाम कोशिशों और ईरान युद्ध समाप्त करने तथा होर्मुज जलमार्ग को खोलने पर 'समझौते' के बावजूद, तेल और ऊर्जा संकट रातों-रात खत्म नहीं होगा। समुद्री बारूदी सुरंगों के खतरे के कारण जहाजों का आवागमन अभी भी बहुत कम है और इस मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाने तथा तेल उत्पादन को सामान्य करने में अभी महीनों का समय लग सकता है। ऊर्जा की ये बढ़ती कीमतें और आपूर्ति में रुकावटें आज भी आम जनजीवन और बाजारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर 'सहमति' बनना पश्चिम एशिया के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर तो हो सकती है, लेकिन इस मार्ग से ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को लेकर आशंका और अनिश्चितता के बादल अभी पूरी तरह से छटे नहीं हैं। क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज में आपूर्ति बाधित रहने की आशंका को भारत के लिए केवल एक बाहरी संकट नहीं, बल्कि एक 'रणनीतिक चेतावनी' माना जाना चाहिए। होर्मुज संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समाने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। फरवरी 2026 से होर्मुज जलमार्ग के प्रभाव रूप से बंद होने के कारण भारत के तेल बाजार पर गहरा असर पड़ा है। इस संकट ने साफ कर दिया है कि भारत को अब ऊर्जा सुरक्षा को सिर्फ 'खरीद' के नजरिये से देखना बंद करना होगा और एक दीर्घकालिक, आक्रामक और लचीली रणनीति अपनानी होगी। इस वैश्विक उथल-पुथल से सीख लेते हुए भारत को भविष्य के भू-राजनीतिक संकटों से निपटने के लिए कच्चे तेल के नए आपूर्ति मार्ग खोजने होंगे, अपने स्टोरेज बक्कर को और बड़ा करना होगा तथा आयात-लिंकड ईंधनों पर निर्भरता को से कम करना होगा। दशकों से

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग पर निर्भर रहा है। यदि इस मार्ग से तेल और गैस की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित होती है, तो इसका सीधा गंभीर असर हमारे परिवहन, कृषि, उद्योग, मुद्रास्फीति और समग्र आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। इसका समाधान केवल नए तेल आपूर्तिकर्ता खोजने में नहीं, बल्कि भारत के पूरे ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को नए सिरे से गढ़ने में है।

कच्चे से कंचन: भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन जमीन के नीचे नहीं, बल्कि देश के हर गांव, कस्बे और शहर की सड़कों पर बिखरा पड़ा है। नगरपालिकाओं का ठोस कचरा, कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और जैविक कचरा हर दिन पहाड़ों की तरह जमा हो रहा है। वर्तमान में इस कचरे का एक बड़ा हिस्सा या तो जला दिया जाता है या बिना किसी उपचार के डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया जाता है, जिससे प्रदूषण और बीमारियाँ फैलती हैं। इस कचरे को समस्या नहीं, बल्कि एक 'रणनीतिक राष्ट्रीय संसाधन' माना जाना चाहिए। इसकी संसाधन साहस पर ही भारत को पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक 'राष्ट्रीय कचरा-से-ऊर्जा मिशन' शुरू करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होगा—कचरे के हर एक किलोग्राम से या तो ऊर्जा बने या जैविक उर्वरक बने या फिर राजस्व पैदा हो। इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमें एक बहु-स्तरीय माडल अपनाना होगा। ग्रामीण स्तर-गांवों में उपलब्ध पशुधन के गोबर और कृषि अवशेषों को सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा में बदला जाए, जिससे पंचायतें

खुद आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादक बन सकें। जिला स्तर-गांवों के समूहों को मिलाकर बायो-मीथेन और केंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयाँ स्थापित की जाएँ, जो स्थानीय उद्योगों और परिवहन के लिए ईंधन की आपूर्ति कर सकें। शहरी स्तर-नगर निगमों द्वारा एकीकृत कचरा प्रसंस्करण सुविधाएँ बनाई जाएँ, जहाँ जलरी, गैस और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियाँ तैयार हों। राष्ट्रीय स्तर-बड़े पैमाने पर औद्योगिक भागीदारी के साथ विशाल वेस्ट-टू-एनर्जी पार्क विकसित किए जाएँ। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अलग-अलग स्तरों में तेल, गैस, महत्वपूर्ण खनिजों और नई ऊर्जा तकनीकों के अवसरों की पहचान करे। हमें अपनी ऊर्जा खोज को केवल खाड़ी देशों तक सीमित न रखकर

नवाचार एवं तकनीक: भारत की असली ताकत उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं, उसकी युवा मेधा है। सरकार को आइआइटी, एनआइटी, विश्वविद्यालयों और स्कूलों के छात्रों के लिए एक 'राष्ट्रीय कचरा नवाचार चुनौती' शुरू करनी चाहिए। इस प्रतियोगिता को ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। कचरा संग्रहण, पृथक्करण, मीथेन कैपचर और कचरे से बिजली बनाने की सस्ती एवं कुशल तकनीकों को विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष अनुदान, इनक्यूबेशन सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। जब युवा इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो भारत के पास अपनी स्वदेशी तकनीकी होगी।

इसके साथ ही, कचरा प्रबंधन में एआई और भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का समावेशन क्रांतिकारी साबित हो सकता है। एआई के माध्यम से कचरा पैदा होने के पैटर्न की पहचान की जा सकती है। कचरा उठाने वाले वाहनों के



विकसित एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए आयातित ऊर्जा पर निर्भरता घटाए भारत।

फाइल

राष्ट्रीय मिशन बने ऊर्जा कूटनीति

चूंकि भारत आने वाले कुछ दशकों तक पूरी तरह से आयात मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए हमारी सुरक्षा वास्तुकला में चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ 'ऊर्जा कूटनीति' होना चाहिए। जिस तरह रक्षा कूटनीति आज हमारी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है, उसी तरह ऊर्जा कूटनीति को भी एक राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। दुनिया भर में तैनात हर भारतीय राजदूत और राजनयिक मिशन का यह प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि वे अपने संबंधित देशों में तेल, गैस, महत्वपूर्ण खनिजों और नई ऊर्जा तकनीकों के अवसरों की पहचान करें। हमें अपनी ऊर्जा खोज को केवल खाड़ी देशों तक सीमित न रखकर

मंगोलिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, अफ्रीका और लाटिन अमेरिका तक फैलाना होगा। विदेश मंत्रालय के भीतर एक समर्पित 'ऊर्जा कूटनीति ढांचा' स्थापित किया जाना चाहिए। भारतीय दूतावासों से मिलने वाले इनपुट की समीक्षा एक उच्च-स्तरीय 'ऊर्जा सुरक्षा परिषद' द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विज्ञानी, उद्योग जगत के नेता और नीति विशेषज्ञ शामिल हों। यह परिषद सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट करे।

आत्मनिर्भरता की ओर पंच वर्षीय पंथान: इस रणनीतिक परिवर्तन को हासिल करने के लिए भारत को एक स्पष्ट समयबद्ध रोडमैप पर चलना होगा। प्रथम वर्ष-देशव्यापी कचरा

मैपिंग, नीतिगत सुधार और पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। द्वितीय और तृतीय वर्ष-ग्रामीण बायोगैस नेटवर्क, जिला प्रसंस्करण केंद्रों और शहरी कचरा-टू-ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। इसके साथ ही स्वदेशी तकनीकों के लिए नवाचार प्रतियोगिताओं का आयोजन। पांचवां वर्ष-भारत को दुनिया की अग्रणी 'वेस्ट-टू-एनर्जी' अर्थव्यवस्थाओं में शुमार करने का लक्ष्य।

इस मिशन की सफलता केवल पैरों की गई मेगावाट बिजली से नहीं, बल्कि साफ शहरों, कम होते हासिल करने के लिए भारत को एक स्पष्ट समयबद्ध रोडमैप पर चलना होगा। प्रथम वर्ष-देशव्यापी कचरा

श्री राम शा

रूट को अनुकूलित कर परिवहन लागत घटाई जा सकती है। स्मार्ट बिन और संस्कार-आधारित प्रणालियाँ से कचरे को सटीक का सटीक पता लगाया जा सकता है, जिससे रीसाइक्लिंग की उत्पादकता कई गुना बढ़ जाएगी। जब तक कचरे को आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह जनआंदोलन नहीं बन सकता। कचरा अलग करने वाले नागरिकों को करें में हट, आवासीय सोसायटियों को रीब्रेट और रीसाइक्लिंग करने वाले स्कूलों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। देश के बड़े कारपोरेट घरानों को 'ग्रीड लै' एक जिला' नीति के तहत एकीकृत कचरा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के

लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जनभागीदारी एवं सौर ऊर्जा का विस्तार: कचरे से ऊर्जा बनाने का संमानांतर, सौर ऊर्जा का विस्तार युद्ध स्तर पर होना चाहिए। सरकार की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' एक शानदार शुरुआत है, लेकिन इसके पैमाने को कई गुना बढ़ाना होगा। भारत की हर छत-चाहे वह घर हो, स्कूल, सरकारी इमारत, फैक्ट्री या मंदिर-मठ-एक मिनी पावर स्टेशन में बदल जानी चाहिए। आसान ऋण, सरल प्रक्रियाओं और लक्षित सब्सिडी के माध्यम से आम जन को ग्रीड में बिजली योगदानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना होगा। केवल नवीकरणीय ऊर्जा रातों-रात हाइड्रोकार्बन

(तेल और गैस) की जगह नहीं ले सकती। इसलिए भारत को एक 'देहरा रणनीति' पर काम करना होगा, जिसके तहत आपूर्ति स्रोतों का रणनीतिक विविधीकरण किया जा सके।

होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए मध्य एशिया, रूस, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना होगा। वैकल्पिक पाइपलाइन कारिडोर, दीर्घकालिक गैस समझौते और एलएनजी बुनियादी ढांचे का विस्तार हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। आधुनिक बंदरगाहों और सुरक्षित समुद्री मार्गों के साथ 'बंगाल की खाड़ी' को भारत के एक नए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उभरना होगा।

✕

पोस्ट

अगर लोग आपको फहाने तो समझिए आप कुछ शक्ति हैं। इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम न करें, जिससे लोग आपको फहचानने से ही इनकार कर दें।
रजत शर्मा@RajatSharmaLive

11 गैदों में 50 सन मारकर वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ पिछले मैच में कई गोलों-गोलों का सारा हिसाब सूर्यवंशी चुकता कर दिया है।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

मैदान पर वैभव सूर्यवंशी की आक्रमकता देखकर उनकी तुलना विराट कोहली से करना ज़्यादा ही है। आइपीएल में आक्रमक खेल दिखाने के बाद तेंदुलकर से उनकी तुलना भी जल्दबाजी थी। यह 15 वर्षीय किशोर क्रिकेटर की मानसिकता पर आघात करने जैसा ही है।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

राम मंदिर में दान और चढ़ावे की ही चोरी नहीं हुई है, बल्कि हिंदू धर्म को बड़ा धक्का मारा गया है। जिन लोगों ने करोड़ों लोगों की श्रद्धा को जैसे तहलुका दिया है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती।

राणा यशवंत@RanaYashwant।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से विश्व में भारत की साफ़ पावर बढ़ी है?

55.3

हैं

26.3

नहीं

18.4

कह नहीं सकते

सभी ऑफ़ वोट प्रत्यक्ष में

आज का सवाल

क्या इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया जाना चाहिए था?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

सूरज बाबा तप रहे इन्द्रदेव नाराज,
धरती तड़पे प्यास से तड़पे कृषक समाज।
तड़पे कृषक समाज नहीं गिर रही फुहारें,
कैसे बोंएँ बीज बिना बूँदें-बौझारें!

फिर पानी सब सूत बिगड़ती सारी सजधज,
करके मद्धिम ताप बूंद बरसाओ सूरज।

-अभि प्रकाश तिवारी

अजय शुक्ला

ajay.shukla
@lko.jagran.
com

राजनीति की धाराएं कुछ सतह के ऊपर, कुछ सतह पर तो कुछ सतह के नीचे बहती हैं। बीते सप्ताह सतह से नीचे बह रही धारा के कुछ सोते सतह पर बुलबुले की तरह फूटकर बहने को बेकरार दिखे। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने एक कार्ययोजना सार्वजनिक की जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुछ विभूतियों पर आधारित 14 नाटकों का मंचन किया जाना है।

इनमें दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला नाम है, राजा सुहेलदेव राजभर का, तो दूसरा नाम है राजा बिजली पासी का। 11वीं शताब्दी के प्रतापी राजा सुहेलदेव की राजधानी श्रावस्ती रही और उनका प्रभाव श्रावस्ती से पूरब की तरफ विस्तार लिए था। आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश भर (राजभर) शासकों और उनके सजातीयों का केंद्र रहा है। राजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के प्रतापी राजा थे। उनका शासन अवध क्षेत्र में विस्तार लिए था।

उत्तर प्रदेश

डायरी

लखनऊ में राजा बिजली पासी के किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं।

जिस तरह भर या राजभर जाति का केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा है, वैसे ही पासी जाति का अवध रहा है। वर्तमान अयोध्या को केंद्र मानकर देखें, तो अयोध्या एवं उसके आसपास से पूरब की तरफ भर जातियों का घनत्व प्रमुखता से दिखता है, तो पश्चिम की तरफ यानी अवध क्षेत्र में पासी समाज का। यहां यह जानना और भी रोचक है कि भर जातियां स्वयं को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की खड़ाऊं रखकर 14 वर्ष शासन करने वाले अनुज भरत से जोड़ती हैं, तो पासी जातियां नाम देवता की उपासक रहीं और स्वयं को शेषावतार लक्ष्मण से जोड़ती रहें हैं।

राजा सुहेलदेव के समकालीन राजा लखन पासी (लखना पासी) नाग देवता के उपासक थे, जिनका किला वर्तमान लक्ष्मण टीला (जनाक टीले वाली लक्ष्मण टीला) के पास बंदो चला रहा है। राजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी के प्रतापी राजा थे। उनका शासन अवध क्षेत्र में विस्तार लिए था।

सतह पर फूट रहे अंतर्धारा के सोते

कंस थे। राजपासी कंस का किला वर्तमान मलिहाबाद के कसमंडी कला में था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। राजपासी कंस ने यहां एक बृहद शिवालय का निर्माण कराया था जहां अब कुछ हिस्से में एक मस्जिद के अवशेष हैं। हाल के दिनों में पासी समाज द्वारा यहां से मस्जिद हटाए जाने को लेकर आंदोलन हुआ और अवशेषों को संरक्षित किए जाने की मांग उठी।

विदेशी आक्रांताओं ने जब इस्लाम के विस्तार के लिए उत्तर भारत की ओर रुख किया, तो उनके शासक तैयार सैद्ध सालार मसूद गाजी का सामना अवध में पासी योद्धाओं लखन पासी एवं राजपासी कंस से हुआ था। दोनों ने बीरता से मुकाबला किया और सालार मसूद की सेना की कमर तोड़ दी। दुर्भाग्य से दोनों ही पासी राजा युद्ध में खेत रहे। किंतु इसका परिणाम यह रहा कि सालार मसूद राजा जी जब श्रावस्ती की ओर बढ़ता हुआ बरगइच पहुंचा, तो राजा सुहेलदेव राजभर ने वहीं उसकी कब्र खोद दी। बीते अडीले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतेंदु नाट्य अकादमी



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर राजा सुहेलदेव राजभर एवं राजा बिजली पासी जैसी विभूतियों पर नाटक तैयार किए जा रहे हैं, जिनका मंचन प्रदेश में किया जाना है। फाइल

के नाटक आनंद मंठ की प्रस्तुति के समय विचार दिया था कि ऐसी गुप्तनाम विभूतियों के योगदान पर आधारित नाटक तैयार कर मंचन किया जाए जिन पर अब तक ध्यान नहीं गया। इसी के बाद सुहेलदेव एवं बिजली पासी पर नाटक तैयार किए जा रहे हैं, जिनका

मंचन प्रदेश के सभी जिलों में किया जाना है।

इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। भाजपा ने हिंदुत्व की छतरी तले जिन विभूतियों को राम मंदिर आंदोलन के बहाने एकत्र किया था, विपक्ष ने चुपके से इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में सेंध लगा ली और सीएसडीएस एवं लोकनीति के सर्वे के अनुसार अवध क्षेत्र में भाजपा को पासी (अनुसूचित जाति) और पूर्वांचल में भर जातियों (ओबीसी) का वोट नामांतर मिला। यहां तक कि भाजपा के उभार का केंद्र रही अयोध्या में भी सपा के अवधेश पासी सांसद निर्वाचित हो गए, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना गया। जबकि 2014 से 2022 तक पासी समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ रहा था।

विभिन्न आकलनों के अनुसार अनुसूचित वर्ग में पासी समाज जाटव समुदाय के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। यह प्रदेश की कुल अनुसूचित आबादी का लगभग 15 से 16 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 3.5

प्रतिशत मानी जाती है। पासी समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग 45 से 55 लाख के बीच आंकी जाती है और अवध क्षेत्र (जैसे लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और कौशांबी) और पूर्वांचल के कुछ जिलों में इनका राजनीतिक बड़ा प्रभाव माना जाता है।

इसी तरह राजभर समाज की हिस्सेदारी लगभग चार से पांच प्रतिशत अनुमानित है। कुल वोट बैंक के लिहाज से उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 60 लाख से 75 लाख है। राजभर मतदाताओं का मुख्य दबदबा पूर्वांचल के लगभग 18 से 24 जिलों में है। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आसमगढ़, जौनपुर और देवरिया जैसे जिलों की कुछ सीटों पर इस समाज का अकेले 12 से 20 प्रतिशत तक वोट बैंक है। अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव में इन्हें वापस पाले में समेटने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, वे सतह पर दिखने लगे हैं, जो इन नाटकों के माध्यम से और भी स्पष्ट होने जा रहे हैं।

सरकार के ढाई साल का सफर

कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना जता रहा है, तो कोई संसदनात्मक बदलाव को उम्मीद कर रहा है। मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर भविष्य के निर्णयों को लेकर भी विभिन्न आकलन किए जा रहे हैं। मंत्रियों के साथ सामूहिक तथा अलग-अलग हुई बैठकों में विभागवार समीक्षा, जनता से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान और आवश्यक निर्णयों एवं निर्देशों पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। हालांकि सभी की निगाहें विशेष रूप से उन मंत्रियों पर टिकी हैं, जिन्हें कमजोर प्रदर्शन के कारण सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुशासन तिहार के दौरान गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में पंचों और सरपंचों के मंच पर आने पर अपनी पुरी होकर उनका स्वागत करने वाले सेवाभावी मुख्यमंत्री की देर रात तक चली बैठक ने हेकड़ीबाज मंत्रियों के लिए अवश्य चिंता बढ़ा दी। मुख्यमंत्री सहज भाव से स्वयं बताते हैं कि पांचवों कक्षा में अध्ययन

के दौरान पिता के निधन के बाद उन्होंने खेती-किसानी करते हुए अपने भाइयों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी निभाई और उससे आगे कभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखी थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें बिना मांगे प्रशासन, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद सब बिना मांगे मिला है, तो इन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना ही उनका कर्तव्य है। यही ईमानदारी मुख्यमंत्री साय की ताकत थी और उछलने-अकड़ने तथा ढैया चाल चलने वाले मंत्रियों और विधायकों के लिए चुनौती थी।

इनमें कुछ वर्तमान मंत्री हैं, तो कुछ ऐसे पूर्व मंत्री भी हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सके। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी मंत्रियों की कमियों और खामियों की समीक्षा के लिए उपस्थित रहे। इसी समीक्षा के आधार पर प्रदेश

मंत्रिमंडल से लेकर पार्टी संगठन और क्षेत्रीय स्तर तक संघर्षाति बदलावों के कयास तेज हो गए हैं। दूसरी ओर, प्रदेश में विभिन्न गुटों में बंटी कांग्रेस के सामने रहलू गांधी की एक प्रभावी सुत्रधार के रूप में स्थापित करने की चुनौती भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तथा भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव सहित कई महत्वाकांक्षी युवा नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में रहलू गांधी की उपस्थिति को भी सता में वापसी के लिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

हेल्पलाइन पर अधिकारियों की परीक्षा : इधर 10 जून तक चले सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और शिकायतों ने भी सरकार को विभिन्न विभागों की

कार्यप्रणाली से अवगत करा दिया है। राजस्व विभाग सबसे अधिक चर्चा में रहा। मंत्रियों और विधायकों की 'रीलबाजी' भी सवालों के घेरे में रही। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि पिछले वर्ष प्राप्त 40.94 लाख आवेदनों की तुलना में इस वर्ष केवल 7.38 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें शिकायत संबंधी आवेदनों की संख्या भी 82 हजार से घटकर लगभग 30 हजार रह गई है। अब नौ जून से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेल्ललाइन 1076 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शी परीक्षा शुरू हो चुकी है। लगभग दस दिनों के भीतर ही 42 विभागों से संबंधित 34 हजार से अधिक आनलाइन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर 1,200 से अधिक श्रेणियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आठ हजार से अधिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि फिलहाल शिकायतों के समाधान की दर केवल चार प्रतिशत है। प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा की निर्धारित व्यवस्था के तहत बुधवार या गुरुवार को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रशासनिक सक्रियता और जवाबदेही की परीक्षा होगी। इस प्रकार

खरी-खरी

ई-वाकिंग

सीमा देवेंद्र

आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि बिना घर से बाहर निकले ही दस-दस किलोमीटर घूम आते हैं। पहले लोग पार्क में मॉर्निंग वाक करते थे, अब मोबाइल में "ई-वाकिंग" करते हैं। मेरे मोहल्ले की दुबे भाभी तो मुझे रोज टोकती हैं— "अरी बहन, थोड़ा घूम-फिर लिया करो!" मैं भी मुस्कुराकर कह देती हूँ, "भाभी, मैं तो रोज घूमती हूँ, बल्कि आपसे कहीं ज्यादा!"

सुबह उठते ही सबसे पहले वाटरपूप नगर की सैर होती है। वहां पहुंचते ही सैकड़ों लोग सुप्रभात के फूल, सूर्य और मोर लेकर खड़े मिलते हैं। कुछ लोग इतने गुप्त साधक हैं कि आनलाइन रहते हुए भी आफलाइन दिखाई देते हैं। लगता है जैसे डिजिटल हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हों।

फिर धीरे-धीरे फेसबुक चौक की ओर बढ़ती हूँ। यहां पुराने परिचित मिल जाते हैं। कोई अपनी पच्चीस साल पुरानी तस्वीर डालकर युवावस्था का प्रमाण दे रहा होता है, तो कोई रोज अपनी उपलब्धियों का उद्घाटन कर रहा होता है। यहां थोड़ी देर विश्राम भी हो जाता है, क्योंकि लोग लाइक और कमेंट के सहारे ही बातचीत कर लेते हैं।

इसके बाद ईस्टग्राम बाजार का नंबर आता है। यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो पूरा देश माडलिंग पर्यटन और खानपान मंत्रालय में भर्ती हो गया हो। हर वयस्क की जिंदगी किसी फिल्म के ट्रेलर जैसी दिखाई देती है। कोई चाय पीते हुए रील बना रहा है, तो कोई सीढ़ियाँ चढ़ने को भी ऐतिहासिक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत कर रहा है। उधर एक्स नामक अखाड़े में जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। वहां लोग चर्चा कम और कुश्ती ज्यादा करते हैं। सुबह का विश्व शतम तक राष्ट्रीय संकट बन जाता है।

योग दिवस पर लोग एक दिन योग करके तस्वीरें डालते हैं, लेकिन हम जैसे ई-वाकर रोज अंगूठे और अंगुलियों का व्यायाम करते हैं। डाक्टर चाहे जितना पैलस चलने को कहें, हम डिजिटल युग के लोग अब कहीं नहीं रुकते। उन्नाव, हरदोई और कौशांबी) और पूर्वांचल के कुछ जिलों में इनका राजनीतिक बड़ा प्रभाव माना जाता है।

योग

स्व

योग दिवस पर योग करते मुख्यमंत्री विष्णु देव साय।

फोटो वैपीआर

लगातार दो वर्षों तक प्रत्येक जिले में समस्याओं के समाधान के लिए सुशासन तिहार का अभियान चलाने के बाद अब सरकार हेल्ललाइन के माध्यम से एक जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने के प्रयास में जुटी है। इन शिकायतों का ईमानदारी और प्रभावी ढंग से समाधान ही सरकार के भविष्य की दिशा तय करेगा।

दिसंबर तक हो जाएगा भारत-ईयू के बीच एफटीए

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अगले साल फरवरी-मार्च से इस समझौते के लागू होने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेड: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत और 27 देशों का समूह यूरोपीय यूनियन (ईयू) दिसंबर तक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अगले साल फरवरी-मार्च से लागू होने की उम्मीद है। इस साल 27 जनवरी को भारत और ईयू ने 'सबसे बड़ी डील' के लिए बातचीत पूरी होने का एलान किया था।

मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बातचीत के दौरान गोयल ने कहा, अब, लगभग शून्य शुल्क के साथ एक गणना पूरा यूरोपीय बाजार हमारे लिए खुल जाएगा। भारत-ईयू एफटीए के तहत लगभग 93 प्रतिशत भारतीय निर्यात को 27 देशों के ब्रह्म में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगा। जबकि ईयू से लकड़ी कारों और वाहन का आयात सस्ता हो जाएगा। कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय यूनियन का वैश्विक जीडीपी में 25 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार (लगभग 33 ट्रिलियन डॉलर) में एक-तिहाई (लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर) हिस्सा है। कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत करते हुए

इस सप्ताह लांच होंगे तीन मेनबोर्ड आइपीओ

नई दिल्ली, प्रेड: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने से प्राथमिक बाजार में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। इसी के चलते इस सप्ताह तीन मेनबोर्ड आइपीओ लांच होने जा रहे हैं। इसी के साथ भविष्य में और पब्लिक इश्यू आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। काउंटिलिया क्रूज का आपरेटर वाटरवैज लोजर टूरिज्म, जयपुर की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी एडविट ज्वेलर्स और आइटो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सीएसएम टेक्नोलॉजीज कुछ दिनों में अपने पहले पब्लिक इश्यू लांच करेंगे। वहीं पैकेजिंग साल्यूशंस प्रोवाइडर मैक पैकेजिंग अपने आइपीओ का मूल्य दायर तय कर सकती है। इसके अलावा अगले महीने एसबीआई म्यूचुअल फंड आइए लहोने अपना 13 हजार करोड़ रुपये आइपीओ ला सकता है।

डेडिकेटेड रेअर अर्थ कारिडोर पर काम शुरू

2026-27 के बजट में घोषित नीति को जमीन पर उतारने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ विमर्श शुरू

भारी खनिज क्षेत्र रेत से रेयर अर्थ मैनेट निकालकर इस क्षेत्र में रयर अर्थ मैनेट इस्तेमाल कर सकते हैं

इस कदम से आरइएम के लिए चीन पर निर्भरता को काफी हद तक कर सकते हैं कम

54 हजार टन आरईएम का आयात किया 2024-25 में, इसमें 93% हिस्सा चीन से मंगाया गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने 2026-27 के बजट में घोषित डेडिकेटेड रेअर अर्थ कारिडोर (डीआरईसी) को जमीन पर उतारने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ विमर्श शुरू कर दिया है। इन चारों राज्यों के समुद्री तटों पर मिलने वाली भारी खनिज युक्त रेत से रेयर अर्थ मैनेट निकालकर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। लाध्य यह है कि इन चार राज्यों को मिलाकर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक इंटीग्रेटेड हब बनाया जाए, जहां खनिज, प्रसंस्करण, रिसर्च और मैन्यूफैक्चरिंग एक साथ होंगे। यह कदम भारत की वर्तमान 90 प्रतिशत तक की आरईएम के लिए चीन पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।

भारत ने वर्ष 2024-25 में 54 हजार टन आरईएम का आयात किया था, जिसमें 93 प्रतिशत चीन से आया था। जबकि दिसंबर, 2024 से सितंबर, 2025 के दौरान चीन ने जब इसके निर्यात पर अंकुश लगा दिया तो भारतीय आटो कंपनियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की थी कि केंद्र ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को मिलाकर एक समर्पित कारिडोर स्थापित करने में मदद करेगा। इसके तहत सरकारी क्षेत्र की आइआरडीएल लिमिटेड की मौजूदा सुविधाओं, जैसे ओडिशा में रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन प्लॉट, केरल के अलुवा नदी रिकॉइनिंग यूनिट और तमिलनाडु के मन्नवलकुरिची में स्थित संयंत्र को इन

भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का तीसरा सबसे बड़ा भंडार

सरकारी अधिकारियों का कहना है, 'भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार होने की पूरी संभावना है। हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। हम विदेशी निर्र्भरता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। रिकाइनिंग पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके लिए हम अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान और चीन जैसे देशों के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ा रहे हैं।' इनका इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र के अत्याधुनिक उपकरणों (ड्रोन आदि) के अलावा स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड और सोलर एनर्जी आदि में तेजी से बढ़ रहा है। ईवी क्रांति, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इनकी मांग कई गुना बढ़ने वाली है।

4,000 टन है आरईपीएम की खपत अभी

रेयर अर्थ प्रोसेसमेंट मैग्नेट्स (आरईपीएम) की खपत अभी 4,000 टन है और वर्ष 2030 इसका 8,000 टन हो जाने की संभावना है। यह बहुत ज्यादा मात्रा है। खपत का लक्ष्य है कि तब तक कुल खपत का 50 प्रतिशत घरेलू स्तर पर उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार ने नवंबर, 2025 में 7,280 करोड़ रुपये की एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।

कारिडोर के साथ संबंधित किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आरईपीएम के भंडार हो सकते हैं।

भरत भूषण एनकाउंटर के विरोध में ओवरहेड टैंक पर चढ़ा युवक

जागरण संवाददाता, शाहहंशपुर : बिहार में भरत भूषण तिवाड़ी के हुए एनकाउंटर के विरोध में शनिवार रात यहां चार घंटे बखेड़ा हुआ। बिहार पुलिस की कार्रवाई के विरुद्ध शिवम मिश्र ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। उनकी मांग थी कि बिहार में फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कार्रवाई हो। उन्होंने स्थानीय पुलिसकर्मियों पर भी अभद्रता का आरोप लगाया। कहा कि मुझे भी एक मामले में पुलिसकर्मियों ने पीटा... आओ, मुझे भी गोली मार दे। बाद में उनके छह वर्षीय बेटे युवराज ने माइक से भावुक अपील की तब वह टैंक से उतरे।

वाहन चालक शिवम मिश्र शनिवार रात आठ बजे रसोई गैस सिलिंडर लेकर टैंक पर चढ़ गए, जिसमें पाइप लगा था। वह बीच-बीच में गैस का रेग्युलेटर खोलकर आग जलाते, धमकाते थे कि सबकुछ रख कर दूंगा। पुलिसकर्मी तेज सामना में समझते रहे, मगर वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे।

टाटा मोटर्स को मिले 3,400 से अधिक ईवी के आर्डर

मुंबई : वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स को माल दुलाई, लाजिस्टिक्स और यात्री परिवहन के लिए 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों (ई-सीवी) के आर्डर प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने कहा कि इन आर्डर में लगभग 2,000 छोटे वाणिज्यिक वाहन और पिक-अप, 900 ट्रक तथा 500 बसे शामिल हैं। इन वाहनों का उपयोग ई-वाणिज्य, लाजिस्टिक, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुएं बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों, शहर के भीतर परिवहन सेवाओं आदि में किया जाएगा। (प्रेड)

ब्रिटेन संग एफटीए का फायदा उठाने के लिए सामान की गुणवत्ता बढ़ाएं निर्यातक

विशेषज्ञों का कहना है कि 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का पूरा फायदा उठाना है तो भारतीय निर्यातकों को अपने सामान को ब्रिटिश नियामकीय जरूरतों के हिसाब से बनाना होगा। उनका यह भी कहना है कि सरकार को दोनों देशों के बीच हुए कामिहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीईटीए) के बारे में घरेलू उद्योग को बताने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में एक आउटरीच कार्यक्रम करना चाहिए। बता दें कि ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य विभाग ने इस सप्ताह छह शहरों में एफटीए के बारे में बताने के लिए रोड शो की शुरुआत की है, जिससे ब्रिटिश कारोबारियों को समझौते को लागू करने के बारे में तैयार किया जा सके। ला फर्म सैम एंड कंपनी के साझेदार रुद्र कुमार पांडे ने कहा, भारत की तरफ से भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देना जरूरी है ताकि निवेशकों को कानूनी सुरक्षा का भरोसा मिले।

वाणिज्य सचिव राजेशा अग्रवाल ने हाल ही में कहा है कि दोनों देशों के मंत्रियों के बीच बातचीत समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।

क्या है पात्रता

टाप-अप लोन हर किसी को नहीं मिल सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपके पास पहले से लोन हो और उसकी मासिक किस्त समय पर भरी हो। बैंक आपके क्रेडिट स्कोर, आय और लोन चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। अगर आपका रिकार्ड अच्छा है तो लोन मंजूरी की संभावना बढ़ जाती है।



जरूरत पर ही लें लोन

टाप-अप लोन तभी लेना चाहिए जब आपको वास्तव में जरूरत हो और आपके पास आय का रिस्पर सोत हो। अगर आप सिर्फ शौक या अनावश्यक खर्च के लिए लोन लेते हैं, तो यह अग्रे चलकर बोझ बन सकता है।

क्यों है सस्ता विकल्प

टाप-अप लोन की ब्याज दरें आम तौर पर असुरक्षित व्यक्तिगत लोन (अनसिक्योरिड पर्सनल लोन) से कम होती हैं। इसका कारण यह है कि बैंक के लिए जोरिफ्त कम होता है, क्योंकि वह पहले से ग्राहक को जानता है। टाप-अप लोन का इस्तेमाल अक्सर घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, लोन चुकाने जैसे कामों के लिए किया जाता है।



राष्ट्रीय फलक

भ्रामक दावे करने वाले कई खाद्य ब्रांड को एफएसएसएआइ का भेजा नोटिस

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने कई खाद्य ब्रांडों (फूड बिजनेस आपरेटर्स) को नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों पर ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और उत्पाद से जुड़े भ्रामक दावे कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के आरोप हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत की गई है। एफएसएसएआइ ने संबंधित कंपनियों को सुधारात्मक कदम उठाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एफएसएसएआइ ने एक्स पर उन फूड बिजनेस आपरेटर्स की पूरी सूची साझा की है जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें प्लवक मैगो फ्रुट जूस, नेचुरल पनीर, गैर हेल्वी फूड का सिल्वन टोफू किंडर जाय शामिल हैं।

प्लवक मैगो फ्रुट जूस के पैक पर साफ तौर पर "नो एडेड शुगर" (कोई अतिरिक्त चीनी नहीं) का दावा किया गया था। हालांकि, इसकी सामग्री की सूची से पता चला कि इसमें 51 प्रतिशत आम का गुदा और 49 प्रतिशत गन्ने का रस था। नो एडेड शुगर का दावा भ्रामक है। नेचुरल पनीर ब्रांड ने अपनी पैकेजिंग पर "नेचुरल पनीर" नाम का इस्तेमाल किया। यह खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2018 की अनुसूची पांच का उल्लंघन है। गैर हेल्वी फूड - सिल्वन टोफू के लेबल पर 100% वेज लिखा है। पेनेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - किंडर जाय पर "रिच इन मिल्क सॉलिड्स" (दूध के ठोस पदार्थों से भरपूर) का दावा प्रमुखता से दिखाने के लिए सवाल उठाए गए। मेडाइजेन लेब्स के एटम पीडब्ल्यूआर न्हे प्रोटीन एक्सपल के "व्थोर एंड हेल्वी" (शुद्ध और सेहतमंद) और 100% ओर्थोटिक जैसे गुमराह करने वाले दावे पर नोटिस जारी किए गए। सैफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग आयल प्रोडक्ट पर भ्रामक तस्वीरों और "हार्ट प्रो" जैसे दावों के लिए सवाल उठाए गए, जिनसे दिल की सहायता के जुड़े ऐसे फायदों का संकेत मिल सकता है जो प्रमाणित नहीं हैं।

नौ सदस्यीय पर्वतारोही दल ने 'सतोपंथ' पर लहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, उत्तराखड़ी

एक्सेस्ट विजेता प्रवीण राणा के नेतृत्व में नौ सदस्यीय पर्वतारोहण दल ने गंगोत्री हिमालय की कठिन चोटियों में शामिल माउंट सतोपंथ (7075 मीटर) पर सफल आरोहण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभियान के दौरान दल को भारी हिमपात, खराब मौसम, गहरी बर्फ, हिमस्खलन के खतरे और दुर्गम भूभाग जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प के बल पर लक्ष्य हासिल किया।

प्रवीण राणा ने बताया कि अभियान के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वापसी ही एकमात्र विकल्प प्रतीत हो रही थी। लगातार कठिन हालात के चलते एक अन्य पर्वतारोहण दल को बीच में ही अभियान छोड़कर लौटना पड़ा। इन परिस्थितियों को देखकर उनकी टीम के सामने भी कई बार पीछे हटने का विचार आया, लेकिन आत्मविश्वास, टीम भावना और भगवान भोलेनाथ में आस्था ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मास्टरचाइ फुड्स - रामेन नूडल्स की पैकेजिंग पर "100% नेचुरल" और "फ्रेशली मेड" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए गए। इसे "हाई-क्वालिटी आर्गेनिक आटे" से बना बताकर बेचा गया था, लेकिन सामग्री की लिस्ट में आटे को आम "प्रोमियम क्वालिटी स्फेड आटा" बताया गया था। पेनेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - किंडर जाय पर "रिच इन मिल्क सॉलिड्स" (दूध के ठोस पदार्थों से भरपूर) का दावा प्रमुखता से दिखाने के लिए सवाल उठाए गए। मेडाइजेन लेब्स के एटम पीडब्ल्यूआर न्हे प्रोटीन एक्सपल के "व्थोर एंड हेल्वी" (शुद्ध और सेहतमंद) और 100% ओर्थोटिक जैसे गुमराह करने वाले दावे पर नोटिस जारी किए गए। सैफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग आयल प्रोडक्ट पर भ्रामक तस्वीरों और "हार्ट प्रो" जैसे दावों के लिए सवाल उठाए गए, जिनसे दिल की सहायता के जुड़े ऐसे फायदों का संकेत मिल सकता है जो प्रमाणित नहीं हैं।

नौ सदस्यीय पर्वतारोही दल ने 'सतोपंथ' पर लहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, उत्तराखड़ी

एक्सेस्ट विजेता प्रवीण राणा के नेतृत्व में नौ सदस्यीय पर्वतारोहण दल ने गंगोत्री हिमालय की कठिन चोटियों में शामिल माउंट सतोपंथ (7075 मीटर) पर सफल आरोहण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभियान के दौरान दल को भारी हिमपात, खराब मौसम, गहरी बर्फ, हिमस्खलन के खतरे और दुर्गम भूभाग जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प के बल पर लक्ष्य हासिल किया।

प्रवीण राणा ने बताया कि अभियान के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वापसी ही एकमात्र विकल्प प्रतीत हो रही थी। लगातार कठिन हालात के चलते एक अन्य पर्वतारोहण दल को बीच में ही अभियान छोड़कर लौटना पड़ा। इन परिस्थितियों को देखकर उनकी टीम के सामने भी कई बार पीछे हटने का विचार आया, लेकिन आत्मविश्वास, टीम भावना और भगवान भोलेनाथ में आस्था ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

कंपनी को अब तेल और गैस उत्पादक के बजाय 'गैस और तेल' कंपनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अब प्राकृतिक गैस का उत्पादन कच्चे तेल से ज्यादा हो रहा है। - अरुण कुमार सिंह, चेयरमैन, ओएनसी

एफपीआइ ने 2,382 करोड़ के शेयर खरीदे

- 60,471 करोड़ रुपये पर आई जून में एफपीआइ की कुल निकासी
- विश्लेषकों को रुपये में मजबूती से एफपीआइ की वापसी की उम्मीद



डेट एफएआर में 18 हजार करोड़ से ज्यादा निवेश

सरकारी प्रयासों के चलते फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) वाले डेट या बांड में एफपीआइ का निवेश जारी है। 119 जून तक डेट एफएआर में एफपीआइ निवेश 18,780 करोड़ रुपये हो गया है। 13 जून तक यह 13,200 करोड़ रुपये था। इसके साथ एफएआर के जरिये कुल निवेश 33,393 करोड़ रुपये हो गया है। डेट एफएआर को सरकारी बांड भी कहा जाता है।

बीते सप्ताह एफपीआइ निवेश

15 जून	-596.85
16 जून	1014.12
17 जून	2885.14
18 जून	886.08
19 जून	-1806.59

नौ कंपनियों की पूंजी 2.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेड : बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में रही तेजी की बदौलत बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 2.15 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बीएसई के मानक सूचकांक सेंसेक्स में 1,274.95 अंक की वृद्धि रही है। सप्ताह के दौरान भारती एयरटेल का पूंजीकरण सबसे ज्यादा 52,432.67 करोड़ रुपये बढ़ा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सेन एंड टूब्रो, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान युनिलीवर और आइसीआईसीआई बैंक का पूंजीकरण भी बढ़ा है। इसके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का पूंजीकरण घटा है।

भारत ने जून में रूस और यूएई से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेड: जून में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात जहां बढ़ा है वहीं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से तेल की खरीद रिकार्ड स्तर के करीब पहुंच गई है। दरअसल, रियाइनों कंपनियों होमूज के फिर से खुलने से पहले खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैरीटाइम और कम्पैडिटी इंटेलेजेंस फर्म केन्लर के अनुसार, भारत ने 19 जून तक रूस से औसतन 26.60 लाख टन बैरल प्रतिदिन का तेल का आयात किया। जबकि मई में यह आंकड़ा 19.10 लाख बैरल प्रतिदिन था।

19 जून तक यूएई से आयात 6.36 लाख बैरल प्रतिदिन रहा जो मई में आयात किए गए रिकार्ड 6.44

19 जून तक रूस से औसतन 26.60 लाख टन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया, अमेरिका से आयात घटा

बैरल प्रतिदिन से थोड़ा कम है। वेनेजुएला 2.09 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। सऊदी अरब 3.84 लाख बैरल प्रतिदिन के साथ तीसरे स्थान पर है।

केन्लर के मुताबिक, जून में अमेरिका से आयात मई के 2.52 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर 91,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। झूट के चलते रूसी कच्चा तेल आकर्षक बना हुआ है।

सेटेलाइट संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस के साथ सुरक्षा मंजूरी भी जरूरी

नई दिल्ली, प्रेड : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सेटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इसके तहत सेटेलाइट संचार सेवाएं शुरू करने के लिए कंपनियों को डीओटी से लाइसेंस के अलावा केंद्र सरकार से सुरक्षा मंजूरी भी आवश्यक रूप से लेनी होगी।

मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन एक निश्चित वार्षिक शुल्क के साथ नीलामी के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वार्षिक शुल्क सेवा के प्रकार के आधार पर 30 हजार से 50 लाख रुपये तक होगा। साथ ही एक हजार रुपये का नान-रिफंडेबल आवेदन शुल्क देना होगा। डीओटी की ओर से जारी एलन मस्क की स्टारलिन, भारती समूह की यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटकाम जैसी कंपनियों के लिए शर्त रखी गई है कि वे आम ग्राहकों के लिए सेटेलाइट संचार सेवा शुरू करें। सेटेलाइट संचार कंपनियों को आम लोगों के लिए

- विभाग ने सेटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर जारी किया मसौदा
- निश्चित वार्षिक शुल्क के साथ प्रशासनिक माध्यम से होगा स्पेक्ट्रम का आवंटन

सेटेलाइट फोन और ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने से पहले केंद्र से अनुमति लेनी होगी। डीओटी ने मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों से 30 दिन के भीतर टिप्पणियां मांगी हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व प्रमुख सलाहकार सत्य पुन गुप्ता ने कहा कि यह अधिसूचना विभिन्न सेटेलाइट सेवाओं के लाइसेंसधारियों की ओर से सेटेलाइट आधारित सेवाएं के प्रविधान के लिए मांग प्रशस्त करती है। दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी को पहले स्पेक्ट्रम लेने और बाद में कागजी कार्रवाई पूरी करने की इजाजत देने से लालफीताशाही कम होगी और सेवा विस्तार में तेजी आएगी।

जिस पिस्टल से मारा गया सिद्धू मूसेवाला, उसका सफ़लायर गिरफ़्तार

जास, जयपुर : राजस्थान में श्रीगंगानगर पुलिस ने तीन राज्यों के बदमाशों को हथियारों की आपूर्ति करने वाले पंजाब के गैंगस्टर शकील अंसारी उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया है। आरोपित गैंगस्टर रोहित गोदारा एवं गोल्डी बराड़ा का प्रमुख साथी है। पुलिस के अनुसार, आरोपित दोनों गैंगस्टरों के गुणों के लिए हथियारों की सप्लाई करता था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जिस जगना और रलाक पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गई थी, वह पिस्टल शकील ने ही आरोपियों तक पहुंचाई थी। शकील शनिवार को श्रीगंगानगर में एक कारोबारी पर फायरिंग करने के लिए पहुंचा था, लेकिन बारदाद से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना मिल गई। पुलिस ने बाइक सवार शकील को रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग की, जबवही कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। पैर में गोली लगने के बाद शकील बाइक से गिर गया।

ईरान ने वार्ता को दिया 'मीनाब 168' नाम, वेंस बोले-हो नई शुरुआत

पहल ▶ मिसाइल हमले में मारी गई 168 स्कूली बच्चियों के सम्मान में दिया गया यह नाम

अमेरिका और ईरान के बीच 14 सप्ताह की सैन्य सहमति पत्र को लागू करने की दिशा में चल रही कोशिशें

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

स्विट्जरलैंड में रविवार को अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए गए ईरानी प्रतिनिधिमंडल को मीनाब 168 नाम दिया गया है। ईरानी प्रेस का नाम अनुसार ये नाम मीनाब स्कूल पर अमेरिकी-इजरायली टाकहक मिसाइल हमले में मारी गई 168 स्कूली बच्चियों के सम्मान में दिया गया है। इस स्कूल पर 28 फरवरी को युद्ध के पहले ही दिन हमला हुआ था।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने 14-सूत्रीय सहमति पत्र (एमओयू) को लागू करने की दिशा में चल रही कोशिशों के तहत पाकिस्तानी पक्ष के साथ अलग से बातचीत की।

गैरतलब है कि इस एमओयू को इस्लामाबाद में मौरैंडम आफ अंडरस्टैंडिंग नाम दिया गया है। इस पर पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड



स्विट्जरलैंड के बर्जेनस्टाड रिजार्ट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पाक पीएम शहबाज व कतर के पीएम अब्दुलरहमान। एपी



ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिक्यान बोले, बातचीत के नतीजे जल्द दिखेंगे

एएनआइ के अनुसार, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिक्यान ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुए शुरुआती समझौते के तहत कतर में फंसे ईरान के छह अरब डॉलर वापस मिलेंगे। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पेजेशिक्यान ने कहा कि एमओयू की सभी शर्तें ईरान के पक्ष में हैं और इन बातचीतों के नतीजे जल्द दिखाई देंगे। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने जिन चीजों पर पहले रोक लगाने की बात की थी, अब उन्हें ईरानी जनता के अधिकार के तौर पर स्वीकार कर लिया है। अमेरिका की मुख्य चिंता ईरान की परमाणु क्षमता है। इस पर हमारे बलिदान सुप्रीम लीडर पहले ही कह चुके हैं कि हम ये हथियार नहीं चाहते।

ट्रंप, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिक्यान और बतौर मध्यस्थ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने डिजिटल हस्ताक्षर किए थे। रायटर के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अब इस सहमति पत्र पर आमने-सामने हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि आगे इसे लागू करने और फालोअप मेकेनिज्म पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में वार्ता केवल एक दिन के लिए प्रस्तावित है। इस दौरान दो बैठकें होंगी, जिसमें सुबह पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई, जबकि शाम को व्यापक मुद्दों पर अमेरिका के साथ मध्यस्थों की मौजूदगी में बातचीत होगी। वार्ता में

अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति वेंस के अलावा अमेरिकी विशेष दूत स्टीव वित्काफ और सलाहकार जेरेड कुशानर शामिल हैं। वहीं, ईरानी प्रतिनिधिमंडल में गलीबाफ संग विदेश मंत्री अब्बास अराघाची, अली बाघेरी व सेंट्रल बैंक गवर्नर हेम्पती शामिल हैं।

यूक्रेन के हमले में क्रीमिया में चार मरे, ईंधन की विक्री रुकी

मास्को, राषट्र : यूक्रेन के रविवार को रूस और उसके नियंत्रण वाले क्रीमिया पर झोन हमलों में चार लोग मारे गए और 28 घायल हुए हैं। यूक्रेन ने शनिवार-रविवार रात रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के तेल और गैस ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसके चलते वहां पर जनसामान्य, कारोबारों और कारखानों को ईंधन की बिजली रोक दी गई है। रूस क्रेमलीन क्षेत्र में भी यूक्रेन ने झोन हमले से तेल आपूर्ति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वहां पर यूक्रेनी हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। यहाँ रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट, तेल-गैस के ठिकानों, ईंधन आपूर्ति व्यवस्था और बिजलीघरों को निशाना बनाया गया है। क्रीमिया और क्रेमलीन पर ताजा हमलों के बाद आवागमन रोक दिया गया है। दोनों भूभागों को कर्च स्ट्रेट अलग करता है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर नौ घंटे सड़क और रेल यातायात रुका रहा।

हीटवेव की चपेट में आया यूरोप, तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा



कई जगहों पर परिवहन व्यवस्था बाधित हुई और वन्यजीवों व पर्यटन स्थलों पर भी बुरा असर पड़ा

यूरोप में रविवार को गर्मियों की पहली हीटवेव पड़ने पर स्पेन के ला कोरिया बीच पर जुटी लोगों की <<भरी भौड़ी। एएफपी

रोम, राषट्र : यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को हीटवेव का असर दिखा। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इटली में चेतावनी जारी करनी पड़ी। परिवहन व्यवस्था बाधित हुई और वन्यजीवों व पर्यटन स्थलों पर भी बुरा असर पड़ा। कई दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के बाद आठ शहरों में रेड अलर्ट जारी किया। वहीं, फ्रांस ने इमरजेंसी सेवाओं और सेना को आग रोकने के लिए अलर्ट पर रखा है। कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रद्द कर दिए हैं।

म्यूजिक डे पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। रविवार को एक-तिहाई हिस्से लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। जर्मनी में तापमान 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने बर्लिन समेत पूर्वी इलाकों में जबरदस्त तूफान की चेतावनी दी है। स्पेन में रविवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई।

लिनकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल तोड़फोड़ में कई गिरफ्तार : ट्रंप

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्यूथ सोशल' पर जानकारी दी कि 'लिनकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल' में कई विरोधियों को गिरफ्तार किया है।

ट्रंप ने कहा कि विरोधियों को सालों की मजदूरी मिल चुकी है। कहा कि पूल की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 'वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए विरोधियों में ओलींपिक साइक्लिस्ट डेविड हर्न भी शामिल हैं। हर्न पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। हर्न ने कहा कि वे साइक्लिंग के बाद रेनोवेट किए गए रिफ्लेक्टिंग पूल को देखने रुके थे। हर्न के अनुसार, वे सामग्री को झुक देखने के लिए पानी में कूबा किया है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन व ब्रिटेन को शामिल किया है, जिससे बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

अमेरिका में बोर्डिंग स्कूल में अपनी ही कब्र खोदने व उल्टी खाने पर छात्रों को किया मजबूर

नई दिल्ली, जेएनएन

अमेरिकी में न्यूयार्क के अब बंद हो चुके 'फैमिली फाउंडेशन स्कूल' के एक पूर्व छात्र ने आरोप किया है कि इस प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में रहने के दौरान उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उसने 10 मिलियन डॉलर का सिविल मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाया है कि छात्रों को अपनी मजबूर खोदने और खुद की उल्टी खाने जैसी यातनाएं दी जाती थीं। वह 2000 से 2003 के बीच इस स्कूल में पढ़ता था। न्यूयार्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्कूल 2014 में बंद हो गया। स्कूल अधिभावकों से फंडाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। स्कूल ने बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले अंग्रेज परिवार के साथ-साथ स्थानीय पुलिस और स्कूल से जुड़े दूसरे लोगों और संस्थाओं पर भी आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चों की कथित तौर पर कपड़े उतराकर तलाशी ली गई, उन्हें अलमारियों में बंद कर दिया गया और अपनी कब्रें खुद खोदने के लिए मजबूर किया गया। संस्थान के अमीर मालिकों की बचत से स्थानीय अधिकारियों ने इस दुर्व्यवहार को

- ▶ एक पूर्व छात्र ने 10 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर किया है
- ▶ जिस शिक्षक की देखरेख में रखा गया उसने किया यौन शोषण

नजरअंदाज कर दिया। पीड़ित के अनुसार, स्कूल में रहने के दौरान उसे संगीत शिक्षक पाल गीर की देखरेख में रखा गया था। गीर ने टोरेटो की यात्रा के दौरान यौन शोषण किया। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, जब उसने माइक आगिरेस को इस शोषण के बारे में बताया, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक, माइक आगिरेस ने बयान में दावा किया कि स्कूल में रहते हुए उन्हें दुर्व्यवहार की किसी भी घटना की जानकारी नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। आगिरेस और उनके वकीलों ने भी टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया।

पीपीपी ने गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया

इस्लामाबाद, ग्रेट : पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने रविवार को गिलगित-बाल्टिस्तान में मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया। पार्टी चेंबरमैन बिलावल भुट्टो-जरदारी ने अमजद हुसैन को इस शीर्ष पद के लिए नामित किया है। चुनावों के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने 24 सदस्यों वाली गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा में 12 सीटें जीतीं। अमजद हुसैन 2020 से 2025 तक गिलगित-बाल्टिस्तान असंबलित के सदस्य रहे और 2009 से 2014 तक इस क्षेत्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे। इससे पहले, डान अखबार ने खबर दी थी कि पीपीपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के समर्थन से सरकार बनाएगी। यह सरकार पावर शोर्शिंग के फामूले के तहत बनेगी। गडबंघन सरकार बनाने का फैसला आपसी भरोसे, आम सहमति और बातचीत पर आधारित था।

मेरी जिंदगी में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी सबसे अहम: जेडी वेंस

बर्गेनस्टाड (स्विट्जरलैंड), एएनआइ : अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ शांति वार्ता के दौरान एक हल्के-फुल्के मजाक से माहौल को सहज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में दो लोग महत्वपूर्ण हैं—एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पत्रकारों से बातचीत में वेंस ने कहा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को मुलाकात के बाद वह अक्सर यह बात मजाक में कहते रहे हैं। उनके इस बयान के समय शरीफ और मुनीर भी मौजूद थे, जो अमेरिका-ईरान वार्ता में कतर के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने पहुंचे हैं। वेंस ने कहा कि पिछले तीन महीनों में उनकी सबसे ज्यादा बातचीत शायद मुनीर से हुई है। उन्होंने मुनीर की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें कुशल राजनयिक बताया। आंध्र प्रदेश से अमेरिका गए परिवार से जुड़ी उषा और जेडी वेंस की मुलाकात 2010 में येल ला स्कूल में हुई थी। दोनों ने 2014 में हिंदू रीति-रिवाजों को शामिल करते हुए अंतरधार्मिक विवाह किया था। उनके तीन बच्चे हैं। उषा का भारतीय मूल अक्सर अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में सांस्कृतिक विविधता और भारतीय-अमेरिकी समुदाय की पहचान से जुड़ी चर्चाओं को भी सामने ले आता है।

ब्रिटेन में पीएम स्टार्मर आज दे सकते हैं इस्तीफा

लंदन, ग्रेट : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री किए स्टार्मर सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस आशय के संकेत बीते दो दिनों से मंत्रियों, लेबर पार्टी के नेताओं, पार्टी के चंद्रदाताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं से उनकी लगातार मुलाकात से मिल रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार निकाय चुनाव में लेबर पार्टी की हार के बाद से इस्तीफे का दबाव झेल रहे स्टार्मर ने अंततः पद छोड़ने का फैसला किया है। फिलहाल नए नेता की दौड़ में सबसे आगे एंडी बर्नहम नजर आ रहे हैं। खुद स्टार्मर ने संकेत में उनके नाम की सिफारिश कर दी है। देश में लेबर पार्टी के खिलाफ बने माहौल के बीच एंडी बर्नहम ने इसी सप्ताह उत्तर इंग्लैंड की मेकरफील्ड सीट के प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव में जीत हासिल की है। इसलिए अन्य पार्टी नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। स्टार्मर ने साफ किया है कि दो वर्ष पूर्व उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता था लेकिन अब वह हर स्थिति के लिए तैयार हैं। पार्टी में नेता पद के लिए कोई विवाद नहीं है। हमारे लिए एंडी बर्नहम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह भी कहा कि अगर किसी मुकाबले की स्थिति बनती है तो वह उसका सामना करेंगे। वैसे गर्जियन



किएर स्टार्मर। फाइल

अखबार के मुताबिक लेबर पार्टी के करीब 300 सांसद नया नेता चुने जाने के पक्ष में हैं। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री पीटर क्लाइव ने कहा है कि हमारे लिए एक सप्ताहांत मुश्किल भरा है। हमें इस समय राजनीतिक वास्तविकताओं, चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। पीटर ने यह बात स्टार्मर की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर कही है। सूत्रों के अनुसार स्टार्मर जल्द इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन पार्टी में नए नेता का चुनाव होने तक कई हफ्ते 10, डाउनिंग स्ट्रीट में रहकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर सकते हैं।

कतर ने बताया अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का रोडमैप

प्रथम पृष्ठ से आगे

रायटर के अनुसार, कतर के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत शुरू होने की घोषणा करते हुए बताया कि वार्ता के जरिए सहमति पत्र (एमओयू) के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक और स्थायी समझौते तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी अधिकारियों के अलग-अलग समूह गठित किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, एमओयू के क्रियान्वयन, वार्ता की प्रगति की निगरानी और अंतिम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी और फालो-अप समूह भी बनाए गए हैं।

स्विट्जरलैंड में चाक चौकंद सुखा व्यवस्था : एपी के

अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच हाई प्रोफाइल शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड में चाक चौकंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। वार्ता स्थल ओमान के बर्जेनस्टाड रिजार्ट के 50 किलोमीटर के दायरे को हाई सिविलिटी जेन में बदल दिया गया। इसके चलते रेंज में आनेवाले ज्यूरिख एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी पैदा हो गई। हालांकि, इसे कुछ देर में ठीक कर लिया गया। बर्जेनस्टाड के ऊपर सैन्य हेलीकॉप्टरों ने पूरी निगरानी रखी। गड़बड़ी दूर होने के बाद ज्यूरिख हवाई अड्डे से 12 विमान उतरे और 14 विमानों ने उड़ान भरी।

इजरायल ने लेबनान पर बरसाए 1000 किलो के बम : एएनआइ के अनुसार, इजरायल ने लेबनान में रविवार को भी भीषण बमबारी की। इस हमले

के लिए इजरायल ने दक्षिणी लेबनान और बेरुत के रिहायशी इलाकों पर 500 से 1000 किलो तक के बम बरसाए हैं। ये इलाके गाजा पट्टी की तरह नजर आने लगे हैं। शनिवार को हुए हमले में 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल की हिब्रू यूनिवर्सिटी के एक पोल में 92 प्रतिशत इजरायली नागरिकों ने माना कि अमेरिका-ईरान समझौते में तेहरान को ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं केवल आठ प्रतिशत लोग मानते हैं कि पश्चिम एशिया में टकराव में इजरायल विजेता बनकर उभरा है। 90 प्रतिशत का मानना है कि युद्ध के उद्देश्य पूरे नहीं हुए, जबकि 30 प्रतिशत लोग मानते हैं कि पीएम नेतन्याहू को इस युद्ध से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नेतन्याहू ने लेबनान से इजरायली सेना को वापस बुलाने से साफ इन्कार कर दिया है।

खेल जागरण

सूर्यवंशी के 94 रन से भारत-ए ने त्रिकोणीय सीरीज का खिताब जीता, श्रीलंका-ए को हराया

वैभव के तूफान में उड़ा श्रीलंका-ए

दंभुला, ग्रेट : 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी असाधारण प्रतिभा और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 29 गेंदों में 94 रन बनाए, जिससे भारत-ए ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में श्रीलंका-ए को 66 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी में 11 गेंदों में अर्धशतक भी शामिल रहा, जो लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक है। उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत-ए ने नौ विकेट पर 377 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका-ए की टीम 311 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने 45 रन देकर तीन विकेट और स्पिनर विपराज ने 60 रन देकर तीन विकेट लिए।

वैभव की तबड़तोड़ शुरुआत : बल्लेबाजी का न्यूता मिलने पर भारत-ए की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार अंदाज में की। टूर्नामेंट में अब तक शांत रहे इस युवा बल्लेबाज ने पहले ही ओवर से श्रीलंकाई गेंदबाजों

पर हमला बोल दिया। सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 2005 में श्रीलंका के कौरैया वीरसुने द्वारा 12 गेंदों में बनाए गए रिकार्ड को तोड़ दिया। उनकी पहली 11 गेंदों का स्कोर क्रम 4, 4, 4, 6, 6, 0, 6, 4, 4, 6, 6 रहा। उन्होंने पांच चौकों और पांच छकों की मदद से रिकार्ड अर्धशतक पूरा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ताकत और बेहतरीन टाइमिंग का शानदार मिश्रण दिखाया। खास तौर पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लगाए गए उनके छक्के दर्शनीय रहे। सूर्यवंशी और प्रियंश आर्य (39) ने पहले विकेट के लिए 132 रन जोड़े। सूर्यवंशी लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नौवें ओवर में अराचिये ने उन्हें मिडआफ पर कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया। इसके बाद अगले ओवर में आर्या भी आउट हो गए। इसके बाद रतुराज (40) और कप्तान तिलक (67) ने तीसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े और पारी को संभाला। अंतिम ओवरों में विकेट गिरने के

श्रीलंका-ए की अच्छी शुरुआत

नहीं : 377 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका-ए को अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन टीम ऐसा नहीं कर सकी। शीर्ष क्रम के निरोशन डिकवेल्ला, अविष्ठा फर्नांडो और नुवानिदु फर्नांडो पहले 10 ओवर में ही 75 रन के स्कोर तक प्रेवेलियन लौट गए। श्रीलंका की ओर से समरविक्रमा (52) और कप्तान साधन (38) ने चौथे विकेट के लिए 53 रन जोड़े, जबकि वजुज (62) और विजयकांत (39) ने सातवें विकेट के लिए 77 रन की सझेदारी की। हालांकि इतने बड़े लक्ष्य के सामने ये प्रयास नाकाफी साबित हुए और टीम केवल 300 रन का आंकड़ा पार कर सकी।



वैभव सूर्यवंशी

महिला टीम को मिली पहली हार



मैनचेस्टर, ग्रेट : मारिजाने काप की की शानदार पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को आइसिस महिला टी-20 विश्व कप मुकाबले में भारत को छह विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की यह मौजूद विश्व कप में पहली हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने सात विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने काप (81*) और तजमिन ब्रिट्स (40) की बेहतरीन पारी की मदद से 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर 159 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से श्रीचर्णी ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए।

इससे पहले भारत को शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के आक्रामक रुख के कारण भारत ने पावरप्ले में 59 रन बनाए। शेफाली ने 31 रन, जबकि स्मृति ने 17 रन की पारी खेली। हालांकि इसके बाद

न्यूजीलैंड को हराकर महिला टीम ने जीता नेशंस कप

अफ्रिलैंड, ग्रेट : शानदार फार्म को जारी रखते हुए भारतीय महिला हार्की टीम ने रविवार को मेजबान न्यूजीलैंड को फाइनल में 2-0 से हराकर दूसरी बार एफआइएच महिला नेशंस कप का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने अगले सत्र की एफआइएच महिला प्रो लीग में भी अपना स्थान पक्का कर लिया। भारत की ओर से नवनीत कौर ने चौथे मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि सुनेलित्ता टोप्पो ने 15वें मिनट में दूसरा गोल वगकर बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद भारतीय टीम ने बेहतरीन रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए बहुत को अंत तक बरकरार रखा और खिताब अपने नाम किया। फाइनल में लालरेमसियामी को प्लेयर आफ द मैच चुना गया, जबकि दीपिका छह गोल के साथ टूर्नामेंट की संयुक्त शीर्ष स्कोरर रहीं। उन्होंने अमेरिका की एशले



जश मनाती हुई महिला टीम • एवस

भारत ने जीत के साथ अगले सत्र की एफआइएच महिला प्रो लीग में भी अपना स्थान पक्का कर लिया

सेसा के साथ यह सम्मान साझा किया। यह भारत का दूसरा नेशंस कप खिताब है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीता था। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा। टीम ने पूल ए में अमेरिका को 3-2, जापान को 2-1 और उरुग्वे को 3-2 से हराया। इसके बाद सेमीफाइनल में चिली को 6-0 से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई।

आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर 2014 के बाद पहली बार नाकआउट में पहुंची जर्मनी

फैक्ट्री से निकलकर जर्मनी के नायक बने उंडव

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: जर्मनी ने जब पिछला विश्व कप जीता था लगभग उसी वक़्त 17 साल का एक लड़का फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए अपने फुटबालर बनने के सपने को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। सुबह चार बजे उठकर फैक्ट्री जाना और फिर आठ घंटे कीशिफ्ट के बाद सेमी-प्रोफेशनल फुटबाल खेलना। फुटबाल से पेट पालने भर की कमाई ना होने के चलते इसे मजदूरी करनी पड़ती थी। इन दिनों के 12 साल बाद 20 जून 2026 की बीती रात इसी लड़के ने 2014 के बाद जर्मनी को पहली बार फुटबाल विश्व कप के नाकआउट में पहुंचा दिया। नाम याद कर लीजिएगा- डेनियज उंडव।

यजीदी मूल के डेनियज का परिवार उनके जन्म से कई साल पहले अपनी जन्मभूमि छोड़कर जर्मनी आ बसा था। डेनियज बीते कुछ वक़्त से लगातार जर्मनी की फुटबाल टीम के साथ हैं लेकिन क्वोज़लियन को इन पर शतना भरोसा नहीं है, वह डेनियज को शुरूआत में मौका देते ही नहीं ज्यादातर वक़्त यह स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में ही खेलते हैं। शनिवार देर रात भी इन्हें 59वें मिनट में मौका दिया, इस वक़्त तक जर्मनी की टीम 1-0 से पीछे थी। कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में आइवरी कोस्ट ने जर्मनी को परेशान कर रखा था। पहला हाफ जर्मनी के लिए बहुत झुंझलाहट भरा बीता।

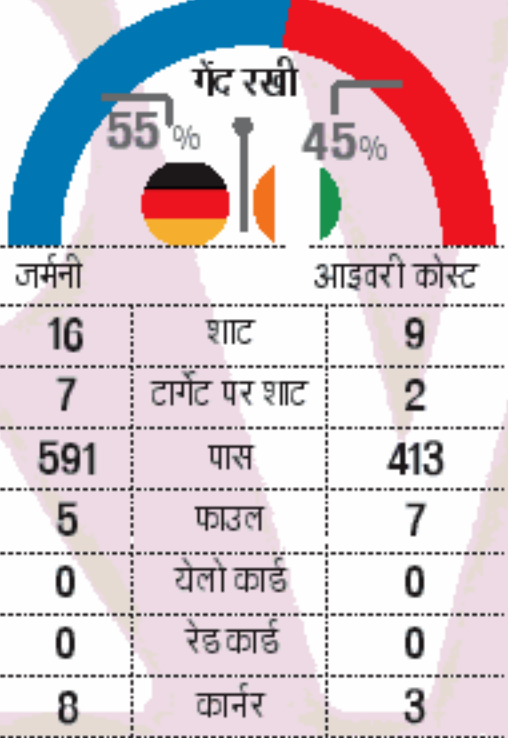
आइवरी के लिए फ्रैंक केरिसिए ने 30वें मिनट में गोल कर दिया, जर्मन डिफेंडर निको श्लोटरबेक चोटिल होकर बाहर जा चुके थे और तो और इसी हाफ में जर्मनी के दो गोल भी अमान्य करार दिए जा चुके थे।

इन स्थितियों के बीच जब मैच में लगभग आधे घंटे का वक़्त बाकी था, उंडव मैदान पर आए। मैच का 68वां मिनट, उंडव के साथ ही मैदान पर आए नदीम अमीरी ने मैदान के बाईं ओर से एक लंबा क्रॉस आइवरी के बाक्स में डाला। काइ हावर्त्स उछले लेकिन गेंद उन्हें पार करते हुए उंडव तक आ गई और उंडव ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए हेडर के जरिए इसे गोल में पहुंचाकर जर्मनी को बराबरी दिला दी।

आइवरी कोस्ट की टीम इससे निराश तो थी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तब कर लिया कि मैच से कम से कम एक अंक तो लेकर ही जाएंगे। निबत 90 मिनट तक वो सफल होते भी दिख रहे थे लेकिन अतिरिक्त समय के चौथे मिनट में उंडव ने उनका दिल ही तोड़ दिया। फेलिक्स मेचा के पास पर उंडव ने घूमते हुए बाक्स के अंदर से ऐसा करारा शूट जमाया कि आइवरी कोस्ट का गोलकीपर जब तक हिल पाता, गेंद गोल के अंदर थी। उंडव इस क्रिक् कप के पहले दोनों मैचों में मिलाकर तीन गोल और दो असिस्ट कर चुके हैं।



2002 के बाद जर्मनी के लिए अपने पहले दो विश्व कप मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने डेनियज उंडव। इससे पहले 2002 में मियोरेलाव क्लोस ने ये कारनामा किया था



आइवरी कोस्ट के विरुद्ध गोल करते जर्मनी के डेनियज उंडव ● एएफपी

1000वें फीफा विश्व कप मैच में नाकआउट के लिए आज आखिरी वार करेंगे मेसी

जमकर चली जापानी तलवार

जापान ने एकतरफा मुकाबले में ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अपनी तलवारबाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध जापान ने फीफा विश्व कप के हजारावें मैच को ऐतिहासिक बना दिया। प्रशंसकों द्वारा ‘बीले समुराई’ बुलाए जाने वाले इन खिलाड़ियों ने अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया को एशियाई फुटबाल का अच्छा पाठ पढ़ाते हुए 4-0 से हराया। जापानी टीम फीफा विश्व कप के किसी एक मैच में इतने गोल करने वाली पहली एशियाई टीम भी बन गई। मैच के चौथे ही मिनट में मिडफील्डर दाइची कमादा ने फारवर्ड कीतो नाकामुरा के असिस्ट पर गोल मार प्रशंसकों को उनकी सीटों पर बैठने से पहले ही उछाल दिया। कमादा के नाम अब फीफा विश्व कप में जापान के लिए सबसे तेज गोल का रिकार्ड दर्ज हो गया है। कमादा ने लीजेंडरी शिंजी कागावा का रिकार्ड तोड़ा जिन्होंने 2018 में कोलंबिया के विरुद्ध छठे मिनट में गोल किया था।

पास्त हुआ ट्यूनीशिया: मैच के 31वें मिनट में ज़्टाडकर अयासे उद्युग्ध ने जापान की बढ़त टोनीली कर दी। पहला हाफ खत्म होने तक स्कोर 2-0 से जापान के पक्ष में था। हालांकि असली खेल तो दूसरे हाफ में हुआ। जापानी टीम पूरी तरह से रंग में आ चुकी थी और उन्होंने ट्यूनीशिया के खिलाड़ियों की तरफ से होते थोड़े-बहुत विरोध को भी कुचलना शुरू कर दिया। ट्यूनीशिया



गेंद के लिए जापानी खिलाड़ी से जुझता ट्यूनीशिया का खिलाड़ी (सफेद) ● एपी

15 गोल बचाकर एलाय बने कुराकाओ की दीवार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: 76 हजार से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला कंसास सिटी स्टेडियम, जहां कुराकाओ की आधी आबादी बैठ सकती है पूरी तरह से पीले रंग में रंगा था। बीच-बीच में किसी कोने पर दो-चार नीली जर्सियां दिख जाती थीं तो लगता था कि मैदान में कुराकाओ की टीम के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुराकाओ अच्छा करे। हालांकि कुराकाओ के गोलपोस्टर की रक्षा में तैनात 37 साल के गोलकीपर

एलाय रूम को किसी की जरूरत नहीं थी। वह अकेले ही पूरे इक्वाडोर को थापने की तैयारी करके आए थे। गुपुई के इस मैच में रूम ने इक्वाडोर को जरा भी क्षम ना देते हुए रिकार्ड 15 शाट बचाए। उनके इस प्रदर्शन की बढील कुराकाओ ने इक्वाडोर को 0-0 की बराबरी पर रोकते हुए पहली बार विश्व कप में कोई अंक हासिल कर लिया। इक्वाडोर के अटेंक्रेट ने कुराकाओ के गोल पर 26 शाट मारे, इनमें से 15 तो निशाने पर ही थे और इन 15 में से एक भी गोल के अंदर नहीं जा पाया। इक्वाडोर ने 75 प्रतिशत वक़्त तक गेंद अपने कंधों में रखी, लगातार गोल पर हमले भी किए लेकिन रूम ने उन्हें एक भी गोल नहीं करने दिया। पिछले मैच में जर्मनी के खिलाफ सात गोल खाने वाले रूम ने जैसे अपना बेस्ट इसी मैच के लिए बचा रखा हो।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अल्जीरिया को 3-0 से हराने और इसमें अपने स्टार लियोन मेसी की शानदार हैटट्रिक से इस फीफा विश्व कप में अपना शानदार आगाज करने वाली गत चैंपियन अर्जेंटीना को टूर्नामेंट के नाकआउट में पहुंचने के लिए सोमवार को आखिरी वार और करना होगा। अमेरिका के टेक्सास के डल्लास स्टेडियम में होने वाले ग्रुप जे के इस मुकाबले में अर्जेंटीना के सामने आस्ट्रिया की चुनौती होगी।

मेसी की हालिया फार्म को देखते हुए दुनिया भर में अर्जेंटीना के समर्थक पहले से ही आस्ट्रिया के विरुद्ध मुकाबले में अपने पक्ष में परिणाम को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि अपने शुरुआती मुकाबले में जार्डन को 3-1 से हराकर शानदार आगाज करने वाली आस्ट्रिया टीम को मेसी की टीम हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। मुकाबले से पहले आस्ट्रिया के दिग्गज मिडफील्डर कानराड लाइमर का कहना है कि मेसी दुनिया

मेसी से आगे निकलना असंभव : लामिने यमाल

अटलांटा, एएनआइ: स्पेन की युवा सनसनी लामिने यमाल ने अर्जेंटीना के लीजेंड लियोन मेसी से आगे निकलने की संभावनाओं को सिर से खारिज कर दिया है। यमाल का मानना है कि मेसी फुटबाल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी बने रहेंगे। उन्होंने कहा, असंभव। मेरे लिए मेसी सर्वश्रेष्ठ हैं और वह इसे साबित भी करते रहते हैं। 40 साल की उम्र में भी वह सबसे बेहतर हैं। यमाल का मानना है कि वह लोगों की अपेक्षाओं से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, लोग जितना सोचते हैं वह उससे भी आगे जा सकते हैं। यमाल के मुताबिक अभी उनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और उनका करियर भी अभी बहुत लंबा चलेगा। यमाल का पूरा ध्यान अपने खेल को बेहतर बनाने पर है।



अभ्यास के दौरान लियोन मेसी ● एएफपी

के सर्वश्रेष्ठ फुटबालर हैं। हालांकि इस गत सीजन में बायर्न म्यूनिख के लिए 47 मैचों में 16 गोल में योगदान देने वाले लाइमर से अर्जेंटीना को भी इसी तरह सतर्क रहने की जरूरत होगी, जिस तरह आस्ट्रिया टीम मेसी के विरुद्ध रणनीति बनाकर आएगी।

ईरानी कोच का अमेरिका पर खराब बर्ताव का आरोप

फीफा विश्व कप डायरी

इराक़ुद्, एपी: ईरान के कोच आमिर घलेनोई ने कहा कि विश्व कप में अमेरिका यात्रा प्रतिबंधों और बीजा अस्वीकृति के जरिए उनकी टीम के साथ अब भी खराब बर्ताव कर रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि फीफा अगले सप्ताह मेजबान देश को इनमें से कुछ कड़े नियमों को कम करने के लिए मना लेगा। घलेनोई ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारा देश हमारे साथ खड़ा है। हम ईरान में अपने शहीदों के लिए खेल रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इस तरह के व्यवहार से हमारे लोगों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अगर हम अरबों डालर खर्च करते हैं तब भी अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। इससे पता चलता है कि हम एक शोषित देश हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमें शांति मिलेगी और विश्व कप में इस तरह का व्यवहार संस्थागत रूप नहीं लेगा। ईरान की टीम रविवार को बेलजियम के विरुद्ध अपने दूसरे मैच के लिए

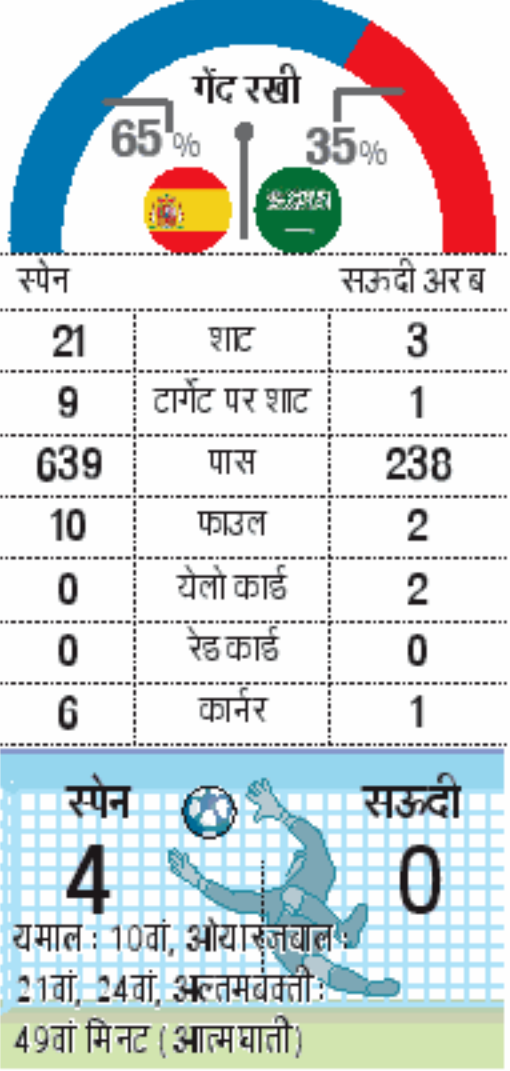


आमिर घलेनोई ● एएफपी

पाएंगे। इससे पता चलता है कि हम एक शोषित देश हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमें शांति मिलेगी और विश्व कप में इस तरह का व्यवहार संस्थागत रूप नहीं लेगा। ईरान की टीम रविवार को बेलजियम के विरुद्ध अपने दूसरे मैच के लिए



गेंद के लिए जुझते यमाल (मध्य) ● एपी



कर चुके थे। उन्होंने 21वें मिनट में अपना पहला गोल भी कर दिया जब सऊदी के डिफेंडर एक कानर पर

एमबापे के हमलों से बचना चाहेगा इराक

ग्रुप आइ के मुकाबले में गत उपविजेता फ्रांस के सामने अब इराक की चुनौती होगी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में होने वाले इस मुकाबले में एमबापे की टीम फ्रांस भी जीत दर्ज कर लाभाना नाकआउट में पहुंच जाएगी। अपने पहले मुकाबले में एमबापे के डबल कमाल से सेमेगल को 3-1 से शिकस्त देने के बाद फ्रांस की टीम के लिए यह मुकाबला जीतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। इराक अपने शुरुआती मुकाबले में नॉर्वे से 4-1 से शिकस्त झेल चुका है, लेकिन सेमेगल के विरुद्ध जिस तरह पहले हाफ में फ्रांस की टीम लय में नजर नहीं आई थी, उससे इराक को भी कुछ आत्मविश्वास मिला होगा।

जार्डन-अल्जीरिया विश्व कप में पहली जीत के लिए वेताब

ग्रुप जे में जार्डन और अल्जीरिया जब सेन फ्रांसिस्को में अमन-सामने होंगे तो दोनों टीम टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेंगी। जार्डन अपने पहले मुकाबले में आस्ट्रिया और

नार्वे को भी परेशान करने की पूरी कोशिश करेगी सेनेगल की टीम

ग्रुप आइ के एक अन्य मुकाबले में नार्वे का सामना सेनेगल से होगा। स्टार एलिंग हालैंड के दो गोल से इराक पर जीत के साथ न्यूयार्क के न्यू जर्सी में होने वाले इस मुकाबले में आ रहे नार्वे को सेनेगल उसी तरह परेशान करने की कोशिश करेगा, जैसे उससे फ्रांस को पहले हाफ में विचलित किया था, हालांकि हालैंड पर ही पूरी तरह से निर्भर यह टीम अपने इस स्टार की हालिया फार्म को देखते हुए इस मुकाबले को लेकर अधिक चिंतित नहीं होगी।

अल्जीरिया अपने पहले मुकाबले में अर्जेंटीना से हार झेलने के बाद इस मुकाबले में आ रहे रहें हैं, हालांकि अब लाभाना बराबर की तकत वाली इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक हो सकता है।

ब्राजील के फारवर्ड राफिन्हा की मांसपेशियों में खिंचाव

न्यू जर्सी, एपी: ब्राजील की राष्ट्रीय टीम ने शनिवार को कहा कि उसके फारवर्ड राफिन्हा मांसपेशियों में खिंचाव का इलाज कराये और एम्मीद है कि वह जल्द ही विश्व कप में वापसी करेंगे। फिलाडेल्फिया में शुक्रवार को हैती पर टीम की जीत के दौरान राफिन्हा को यह चोट लगी थी और मैदान पर चिकित्सा सहायता लेने के बाद उन्हें बाहर रखा पड़ा था। ब्राजील के फुटबाल महासंघ ने

शनिवार को लास एंजेलिस लौट आइं, लेकिन घलेनोई ने कहा कि उनकी टीम इस मैच के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि हमें लास एंजेलिस में 24 घंटे चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हमें 16 घंटे से भी

बाद में कहा कि इस 29 वर्षीय खिलाड़ी की वाहनी जांच की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और उसकी अंगे जांच कराई गई। जांच से खिंचाव की पुष्टि हुई है लेकिन यह ऐसी चोट नहीं जिसके कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। ब्राजील बुधवार को फ्लोरिडा के मियामी गार्ड्स में स्काटलैंड के विरुद्ध ग्रुप चरण का अपना अंतिम मैच खेलेगा।

कम समय दिया और इसी वजह से हमें अपना अभ्यास बीच में छोड़ना पड़ा। घलेनोई ने विश्व कप की अन्य टीमों और कोच से भी ईरानी टीम के साथ किए जा रहे व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील की।

विश्व कप के 33 मैचों में लगा गोलों का शतक

नई दिल्ली, आइएनएस: फीफा विश्व कप 2026 में गोलों की बरसात देखने को मिल रही है। इस सीजन में हुए 33 मैचों में ही 100 गोल का आंकड़ा पार हो चुका है, जो पिछले 68 वर्षों में सबसे तेज है। 1958 के साठ विश्व कप के एक संस्करण में यह सबसे कम मुकाबलों में 100 गोल लगे हैं। मेक्सिको के जूलियन क्विनोनेस ने 12 जून को साउथ अफ्रीका पर 2-0 की जीत में इस विश्व कप में स्कोरिंग की शुरुआत की। नीदरलैंड्स के कोडी गकोपे ने स्वीडन पर 5-1 की जीत में नीदरलैंड्स का तीसरा गोल करके इस साल के टूर्नामेंट का 100वां गोल किया। सिर्फ 33 मैचों में 100 गोल तक पहुंचना 68 साल के टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इससे पहले 1982 और 2014 के विश्व कप में 100 गोल का आंकड़ा 36 मैचों में पूरा हुआ था, जबकि 1978 और 1994 में इसके लिए 38



फीफा विश्व कप 2026 का 100वां गोल दमते नीदरलैंड्स के गकोपो ● राइट

मैच लगे थे। हालांकि, सबसे तेज 100 गोल सिवट्जरलैंड में 1954 में हुए विश्व कप में लगे थे। इस विश्व कप में 100 गोल सिर्फ 20 मैच में लगे थे। उस टूर्नामेंट का खिताब वेस्ट जर्मनी ने जीता था। इसके अलावा, नीदरलैंड्स ने भी एक खास उपलब्धि हासिल की।



क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें या विजिट करें jagran.com

